शिक्षा क्षेत्र की प्रतिनिधि पत्रिका
राष्ट्रीय छात्रशक्ति

राष्ट्रीय छात्रशक्ति

वर्ष-46 ■ अंक-07 ■ नवंबर 2024 ■ ₹10 ■ पृष्ठ-48

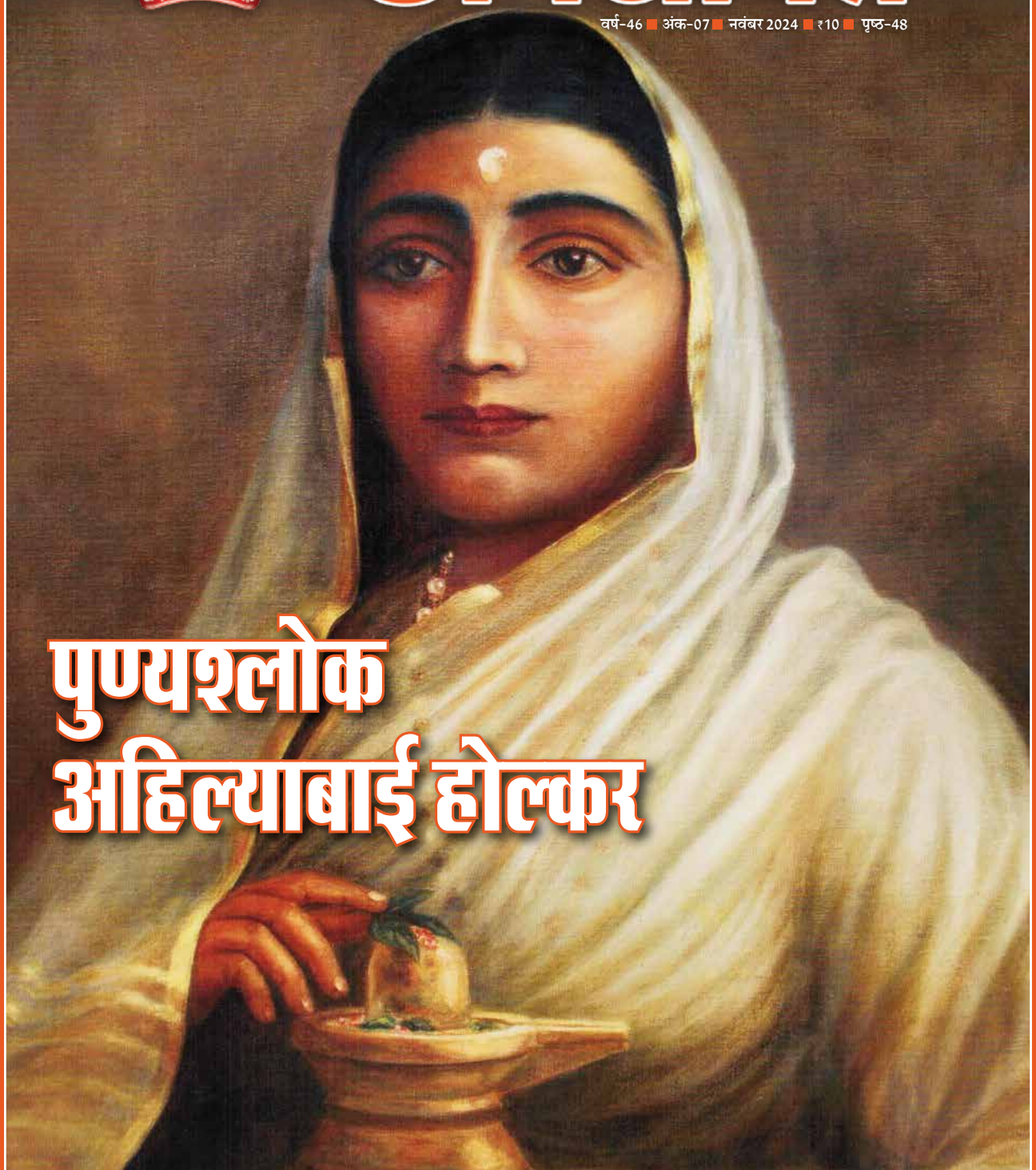

पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होल्कर

भाग्यनगर : रिसर्च स्कॉलर कॉन्कलेव का शुभारंभ करते हुए अभाविप राष्ट्रीय सह-संगठन मंत्री एस. बालकृष्ण, जेएनटीयू (हैदराबाद) के रिसर्च एवं डेवलपमेंट निदेशक प्रा. कामाकाशी प्रसाद, सापला ऑर्गेनिक लि. कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. वाई रेड्डी, अभाविप तेलगांना प्रांत अध्यक्ष जेना रेड्डी, प्रांत मंत्री कुमारी झांसी एवं प्रांत शोध संयोजक ए. श्रीधर

गोरखपुर : छात्र दैनंदिनी-2025 का विमोचन करते हुए अभाविप राष्ट्रीय अध्यक्ष डा. राजशरण शाही, महामंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल, संगठन मंत्री आशीष चौहान, मंत्री वीरेन्द्र सोलंकी, मुस्तफा अली, अंकित शुक्ल, श्रवण बी. राज, बुद्धदेव बाघ, राहुल राणा, केन्द्रीय कार्यालय मंत्री दिगंबर पवार एवं अन्य छात्र नेता।

आवरण चित्र

राष्ट्रीय
छात्रशक्ति
शिक्षा क्षेत्र की प्रतिनिधि पत्रिका

वर्ष-46, अंक-07
नवंबर 2024

संपादक
आशुतोष भटनागर
संपादक-मण्डल :
संजीव कुमार सिन्हा
अवनीश सिंह
अभिषेक रंजन
अजीत कुमार सिंह

संपादकीय पत्राचार :
राष्ट्रीय छात्रशक्ति
26, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग,
नई दिल्ली - 110002.
फोन : 011-23216298
www.chhatrashakti.in
rashtriyachhatrashakti@gmail.com
www.facebook.com/Rchhatrashakti
www.twitter.com/Rchhatrashakti
www.instagram.com/ Rchhatrashakti

स्वामी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक **राजकुमार शर्मा** द्वारा 26, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, आई.टी.ओ. के निकट, नई दिल्ली - 110002 से प्रकाशित एवं ओशियन ट्रेडिंग कं., 132 एफ. आई. ई., पटपड़गंज इण्डस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली-110092 से मुद्रित। **संपादक** *पीआरबी अधिनियम के तहत समाचारों के चयन के लिए जिम्मेवार।

अबकी बार

10 **लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर**

भारत भूमि प्राचीनकाल से ही महान महिलाओं की पृष्ठभूमि रही है। अनेकानेक महिलाओं ने भारत के इतिहास में स्वर्णिम स्थान अर्जित किया है। ऐसे ही महान विभूतियों...

संपादकीय	04
गोरखपुर में होगा लघु भारत का दर्शन	05
भारत ने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी-एशिया रैंकिंग में मारी बाजी	09
आदर्श राज व्यवस्था की प्रणेता	14
साहित्य एवं कला को प्रोत्साहन	17
नारी शक्ति की प्रतिमूर्ति	21
विद्यार्थियों की आर्थिक बाधाओं को दूर करेगी पीएम विद्यालक्ष्मी योजना	25
75 Years of Constitution of Bharat	26
बीएचयू कुलपति से मिला अभाविप प्रतिनिधिमंडल	28
...नहीं रही स्वर कोकिला शारदा सिन्हा	29
भारत के स्वर्णिम इतिहास का साक्षी वैशाली गणतंत्र	30
'पर्यावरण अनुकूलन के लिए कार्य करें विद्यार्थी'	33
सिक्किम विश्वविद्यालय में अभाविप की ऐतिहासिक जीत	34
दीपोत्सव कार्यक्रम में पांथिक उन्मादियों ने फैलाई हिंसा	35
भारतरत्न नानाजी देशमुख की जयंती पर देशव्यापी सेवा सप्ताह का आयोजन	36
लोक सेवा आयोग ने स्वीकारी अभ्यर्थियों की मांग	37
ABVP and JU Host India-Germany Youth Dialogue in Bengaluru	38
SHoDH Hosts Inspiring "Research for Radiant Bharat" Conclave in Bhagyanagar	40
Donald Trump's Presidency and its far-reaching impact on India	42
वीआईटी विश्वविद्यालय में अवैध रूप से हुई कुलगुरु की नियुक्ति	45
'राष्ट्र की उन्नति के लिए काम कर रही है अभाविप'	46

वैधानिक सूचना : राष्ट्रीय छात्रशक्ति में प्रकाशित लेख एवं विचार तथा रचनाओं में व्यक्त दृष्टिकोण संबंधित लेखकों के हैं। संपादक, प्रकाशक एवं मुद्रक का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है। समस्त प्रकार के विवादों का न्यायिक क्षेत्र दिल्ली होगा।

संपादकीय

26 नवंबर को संविधान दिवस है। इस वर्ष भारतीय संविधान की रचना पूर्ण होने का 75वां वर्ष प्रारंभ हो रहा है जो आपातकाल के संक्षिप्त विराम को छोड़, इस यात्रा की निरंतरता का उत्सव है।

भारत के साथ ही स्वतंत्र हुए पड़ोसी देशों में उनके संविधानों के साथ बार-बार छेड़छाड़ का इतिहास मिलता है। उनके संविधानों की रचना भी बदलती सत्ता की रुचियों के अनुसार बदलती गई क्योंकि उनकी रचना के पीछे कोई राष्ट्रीय अथवा ऐतिहासिक दृष्टि नहीं थी। भारत का संविधान न केवल सुचिंतित है, अपितु भारतीय दर्शन, परम्परा और लोकजीवन के विभिन्न आयामों को समेटता हुआ एक ऐसा दस्तावेज है जो प्रत्येक भारतीय को अपने विचारों की अभिव्यक्ति लगता है।

भारत में गणतंत्र अनादि काल से चला आ रहा है। इसीलिए पिछले कुछ समय से इसे "भारत- लोकतंत्र की जननी" के नाम से संबोधित किया जा रहा है। वैशाली और लिच्छिवी गणराज्य से पूर्व भी भारत के एक बड़े भू-भाग में यादवों के गणतंत्र थे, जिनमें सभा और समितियों के माध्यम से जनप्रतिनिधित्व और सामूहिक नेतृत्व जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों का दर्शन होता था।

संविधान निर्माण के लिए चुनी गई संविधान सभा में न केवल ब्रिटिश भारत, अपितु रियासतों के प्रतिनिधियों का समुचित प्रतिनिधित्व था। इसके बाद भी भारत में जुड़ने वाली रियासतों की पहली विधानसभा को अपने राज्य की आवश्यकताओं के अनुरूप संवैधानिक सुधारों को प्रस्तावित करने की छूट दी गई थी। यह संविधान सभा की सामूहिक प्रज्ञा का ही उदाहरण है कि उसमें अनेक प्रावधान ऐसे जोड़े गए जिन्होंने भविष्य में होने वाली समस्याओं की संभावनाओं को उत्पन्न होने से पहले ही टाल दिया।

पूज्य डा. बाबासाहब आंबेडकर द्वारा 'फेडरेशन' के स्थान पर 'राज्यों के संघ' शब्द का प्रयोग और प्रस्तावना में 'बंधुत्व' शब्द जोड़ा जाना, उनकी राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि की गहनता को प्रकट करता है।

यद्यपि विलायत से पढ़कर लौटे कतिपय नेता इसे अंग्रेजों की देन और 'नेशन इन मेकिंग' मानते थे परन्तु उसी संविधान सभा में बहुसंख्य सदस्य ऐसे थे, जो भारतीयता के भाव से ओत-प्रोत थे। उनके ही आग्रह के चलते संविधान की मूल प्रति में प्रत्येक अध्याय के प्रारंभ में भारत के सांस्कृतिक-दार्शनिक आख्यान को स्मरण कराने वाले चित्रों का संयोजन किया गया, जो इसे भारत की सांस्कृतिक निरंतरता से जोड़ता है।

संविधान में प्रयुक्त एक-एक शब्द और उसकी व्याख्या को लेकर लंबी चर्चा हुई। वाद-प्रतिवाद हुए। अंततः सदन ने जिसे स्वीकृति दी वह आज भी उतना ही प्रासंगिक है। पूज्य डा. बाबासाहब आंबेडकर द्वारा 'फेडरेशन' के स्थान पर 'राज्यों के संघ' शब्द का प्रयोग और प्रस्तावना में 'बंधुत्व' शब्द जोड़ा जाना उनकी राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि की गहनता को प्रकट करता है। सभी राज्यों को अपनी परिस्थितियों के अनुरूप संविधान बनाने का अवसर देना, उनके कठिनाई अनुभव करने पर उन्हें आदर्श संविधान उपलब्ध कराना और अंततः उसे भारतीय संविधान के अंगीभूत घटक के रूप में स्वीकार कर उन राज्यों की जनता के मन में केन्द्रीय संविधान के प्रति विश्वास प्राप्त करने की अनूठी पहल थी।

यही कारण है कि आपातकाल के अंधेरे से संविधान को बचाने के लिए सभी वर्ग और समूह एकजुट होकर आगे आए और केवल उन्नीस माह में ही वह अंधियारा छंट गया। हर सकारात्मक परिवर्तन को आत्मसात करने वाला यह संविधान एक जीवंत दस्तावेज है जो प्रत्येक भारतीय के जीवन को स्पर्श करता है। 75वें वर्ष का यह अवसर भारतीय गणतंत्र को और अधिक सुदृढ़ करने और सर्वसमावेशी बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर सिद्ध होगा यह विश्वास है।

गुरु गोरखनाथ जी की तपस्थली में आयोजित परिषद के राष्ट्रीय अधिवेशन में उपस्थित प्रतिनिधि इस दिव्य क्षेत्र की आध्यात्मिक ऊर्जा और सांस्कृतिक चेतना की अनुभूति लेकर अपने कार्यक्षेत्र में जाएंगे तो उनके प्रयास अवश्य सुफलदायी होंगे।

हार्दिक शुभकामना सहित

आपका
संपादक

गोरखपुर में होगा लघु भारत का दर्शन

गुरु गोरखनाथ की पावन धरा पर स्थित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय के प्रांगण में अहिल्याबाई होल्कर नगर के निर्माण का कार्य तेजी से जारी है। अस्थाई रूप से बनाए जा रहे अहिल्याबाई होल्कर नगर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) का 70वां राष्ट्रीय अधिवेशन आगामी 22 नवंबर से आरंभ होगा। तीन दिवसीय अधिवेशन के लिए बनाया जा रहा विशाल सभागार भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नायक अमर बलिदानी रामप्रसाद बिस्मिल को समर्पित किया गया है, जबकि अधिवेशन के दौरान लगाई जाने वाली प्रदर्शनी के माध्यम से विश्व प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर के पूर्व पीठाधीश्वर एवं सामाजिक समरसता के अग्रदूत महंत अवेद्यनाथ के जीवन से जुड़े विभिन्न उदान्त पक्षों को सामने रखा जाएगा, जो सभी प्रांतों से अधिवेशन में आने वाले प्रतिभागियों में नई ऊर्जा का संचार करेंगे। तीन दिवसीय अधिवेशन में सहभागी होने वाले प्रतिनिधि शिक्षा क्षेत्र में विभिन्न परिवर्तनों की समसामयिक स्थिति

पर चर्चा करेंगे। साथ ही संगठनात्मक, रचनात्मक, आंदोलनात्मक विषयों तथा लक्ष्यों का निर्धारण करने के लिए मंथन किया जाएगा। अभाविप को भारत की युवाशक्ति के प्रतिनिधि संगठन होने के कारण इस दायित्व का बोध भी है कि भारत के समसामयिक मुद्दों और चुनौतियों के समाधान में युवाओं की भूमिका क्या होगी? इस विषय पर भी विचार किया जाएगा।

वैदिक मंत्रों के साथ भूमि पूजन

70 वें राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में निमित्त कार्यक्रम स्थल पर गत 8 नवंबर को 51 पुरोहितों द्वारा वैदिक मंत्रों के साथ भूमि पूजन संपन्न हुआ। भूमि पूजन के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (गोरक्ष प्रांत) के प्रांत प्रचारक रमेश, सह प्रांत प्रचारक सुरजीत, केंद्रीय विश्वविद्यालय (गया) के कुलपति प्रो. के. एन. सिंह, राजा महेंद्र प्रताप सिंह अलीगढ़ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. चंद्रशेखर, गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. शांतनु रस्तोगी, पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के क्षेत्रीय संगठन मंत्री घनश्याम शाही एवं गोरक्ष प्रांत अध्यक्ष डा. राकेश प्रताप सिंह भी उपस्थित रहे।

भूमि पूजन के अवसर पर गोरक्ष प्रांत के प्रांत प्रचारक रमेश ने कहा कि आधुनिकता के साथ विद्यार्थी अपनी मूल जड़ों से भी परिचित रहें तथा भारत की एक राष्ट्र के रूप में सतत प्रवाहमान यात्रा के स्वरूप को समझ सकें, इसके लिए अधिवेशन में विभिन्न प्रयास करने की योजना बनाई गई है। गुरु गोरखनाथ की पावन धरा पर आयोजित होने जा रहे राष्ट्रीय अधिवेशन में देश के विभिन्न प्रांतो से आने वाली छात्रशक्ति का संगम भारत की अनेकता में एकता के भाव को प्रदर्शित करेगी।

श्रीधर वेम्बू होंगे राष्ट्रीय अधिवेशन के मुख्य अतिथि

70वें राष्ट्रीय अधिवेशन में मुख्य अतिथि के रूप में जोहो कॉर्पोरेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीधर वेम्बू सम्मिलित होंगे। राष्ट्रीय अधिवेशन में वह प्रतिनिधियों को संबोधित भी करेंगे।

उल्लेखनीय है कि तकनीकी उद्योग एवं उद्यमिता क्षेत्र में आत्मनिर्भरता एवं स्थानीय प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने में श्रीधर वेम्बू की भूमिका भारत सहित पूरे विश्व के युवाओं के लिए प्रेरणादायक है। भारत के तकनीकी विकास, ग्रामीण उत्थान और शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव लाने का उनका प्रयास वर्तमान में भारतीय युवाओं को एक सही रास्ता दिखाता है। श्रीधर वेम्बू ने तमिलनाडु के तेनकासी जिले में जोहो कार्पोरेशन कंपनी की आरंभ कर स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए। अपनी प्रतिभा तथा पुरुषार्थ के माध्यम से उन्होंने ग्रामीण जीवन को उन्नत तकनीक से जोड़ने तथा तकनीकी उद्यमशीलता से जोड़ने का जो प्रयत्न किया, वह अनुकरणीय है।

छात्र दैनंदिनी-2025 का विमोचन

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) की छात्र दैनंदिनी (वार्षिक डायरी) का विमोचन गत 27

अक्टूबर को गोरखपुर में किया गया। इस अवसर पर अभाविप के राष्ट्रीय अध्यक्ष डा. राजशरण शाही, राष्ट्रीय महामंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल, राष्ट्रीय संगठन मंत्री आशीष चौहान, राष्ट्रीय मंत्री वीरेन्द्र सोलंकी, मुस्तफा अली, अंकित शुक्ल, श्रवण बी. राज, बुद्धदेव बाघ, राहुल राणा, केन्द्रीय कार्यालय मंत्री दिगंबर पवार सहित अन्य छात्र नेता उपस्थित रहे।

2025 की दैनंदिनी के मुख्य पृष्ठ पर पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होल्कर, शिक्षा में भारतीयता, भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय गणित, विज्ञान, शिक्षा का नवसंचार, भारतीय भाषा में शिक्षा का महत्व, समाज परिवर्तन हेतु पंच परिवर्तन आदि का उल्लेख किया गया है। नई छात्र दैनंदिनी में संगठनात्मक विषयों की संक्षिप्त जानकारी, पर्वों का उल्लेख, कैलेंडर इत्यादि की जानकारी के साथ भारतीय युवाओं की आकांक्षाओं तथा भारत की प्रगति को दर्शाया गया है।

डा. शाही राष्ट्रीय अध्यक्ष और डा. सोलंकी बने नए राष्ट्रीय महामंत्री

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और महामंत्री के रूप में डा. राजशरण शाही तथा डा. वीरेन्द्र सिंह सोलंकी को निर्वाचित किया गया है। निर्वाचन प्रक्रिया मुंबई स्थित अभाविप के केन्द्रीय कार्यालय से सम्पन्न हुई। गत 8 नवंबर को निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न होने के बाद राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद के विशेष आमंत्रित सदस्य प्रो. प्रशांत साठे ने बताया कि नवनियुक्त पदाधिकारी अभाविप के 70वें राष्ट्रीय अधिवेशन में अपना कार्यभार संभालेंगे।

जानकारी हो कि डा. राजशरण शाही मूलतः उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के निवासी हैं। शिक्षाशास्त्र विषय में पीएचडी करने वाले डा. शाही लखनऊ स्थित बाबासाहब भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय शिक्षाशास्त्र विभाग में आचार्य एवं विभागाध्यक्ष होने के साथ ही शिक्षा संकाय के अधिष्ठाता के पद पर कार्यरत हैं। उत्तर प्रदेश की विभिन्न शैक्षिक एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के क्रियान्वयन संबन्धी महत्वपूर्ण समितियों के सदस्य डा. शाही, शिक्षा एवं सामाजिक विषयों के गहन चिंतक हैं। अभाविप कार्य को आगे

बढ़ाने में महती भूमिका का निर्वहन करने वाले डा. शाही 1989 से अभाविप के कार्य को करते आ रहे हैं। शिक्षक कार्यकर्ता के रूप में गोरखपुर महानगर अध्यक्ष से लेकर गोरक्ष प्रांत अध्यक्ष तथा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदि दायित्वों का निर्वहन कर चुके डा. शाही 2024-25 हेतु राष्ट्रीय अध्यक्ष के दायित्व पर पुनर्निवाचित हुए हैं।

अभाविप के राष्ट्रीय महामंत्री के लिए निर्वाचित डा. वीरेंद्र सिंह सोलंकी मध्य प्रदेश के निवासी हैं। मेडिकल की शिक्षा लेने वाले डा. सोलंकी शासकीय स्वशासी अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय (इंदौर) में चिकित्सक के रूप में अल्पकालिक सेवा में कार्य कर रहे हैं। 2014 से अभाविप के लिए सक्रिय डा. सोलंकी ने अभाविप के एलोपैथी विद्यार्थी कार्य-मेडीविज़न के माध्यम से आयुर्विज्ञान एवं दंत चिकित्सा शिक्षा के विद्यार्थियों में राष्ट्रीय नेतृत्व प्रदान कर विभिन्न मुद्दों के सफल नियोजन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है।

प्रा. केलकर युवा पुरस्कार-2024 दीपेश नायर को

प्रा. यशवंतराव केलकर युवा पुरस्कार-2024 की चयन समिति ने वर्ष 2024 के पुरस्कार के लिए 'ट्रेनिंग एंड एजुकेशनल सेंटर फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड' (टीच) के सह-संस्थापक दीपेश नायर का चयन किया है। दीपेश नायर बधिर तथा कम सुनाई देने संबंधी दिव्यांगता से प्रभावित विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा क्षेत्र में समान अवसर उपलब्ध कराने हेतु पारिस्थितिकी तंत्र निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। उनका लक्ष्य है कि श्रवण दिव्यांगता से प्रभावित विद्यार्थी व्यक्तिगत, पेशेवर और सामाजिक विकास करते हुए अपने जीवन को स्वतंत्र, सम्मानजनक और सफल दिशा दे सकें।

दीपेश नायर को यह पुरस्कार गोरखपुर में आयोजित होने वाले अभाविप के राष्ट्रीय अधिवेशन में प्रदान किया जाएगा। यह पुरस्कार 1991 से प्राध्यापक यशवंतराव केलकर की स्मृति में दिया जाता है। प्रा. केलकर को अभाविप संगठन का शिल्पकार कहा जाता है। यह पुरस्कार अभाविप और विद्यार्थी निधि न्यास की एक संयुक्त पहल है, जो छात्रों की उन्नति एवं शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए प्रतिबद्ध विभूतियों को प्रदान किया जाता है। प्रा. केलकर पुरस्कार का उद्देश्य युवा सामाजिक उद्यमियों के काम को समाज के सामने लाने, उन्हें प्रोत्साहित करने और उनका समाज कार्य में योगदान करने के लिए प्रदान किया जाता है। पुरस्कार में एक लाख रुपए की धनराशि, प्रमाण पत्र एवं स्मृति चिह्न समाविष्ट हैं।

इस वर्ष प्रा. केलकर युवा पुरस्कार के लिए चयनित दीपेश नायर ने बधिर तथा कम सुनाई देने संबंधी दिव्यांगता से प्रभावित छात्रों हेतु उच्च शिक्षा मॉडल निर्माण के उद्देश्य से 'ट्रेनिंग एंड एजुकेशनल सेंटर फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड' (टीच) की स्थापना की है। इसका लक्ष्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और करियर के अवसर प्रदान करना है। दीपेश नायर ने 2016 में 'ट्रेनिंग एंड एजुकेशनल सेंटर फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड' की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्कूलों और गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) में शिक्षण से उनकी यह यात्रा आरम्भ हुई थी। 'ट्रेनिंग एंड एजुकेशनल सेंटर फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड' का यह मॉडल छात्रों को उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान करता है।

'मानवंदना यात्रा' का शुभारंभ

पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होल्कर के त्रिशताब्दी वर्ष के

अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) द्वारा आयोजित 'मानवंदना यात्रा' आगामी 21 नवंबर को गोरखपुर में आयोजित होने जा रहे राष्ट्रीय अधिवेशन में पहुंचकर समाप्त होगी। मानवंदना यात्रा का शुभारंभ अभाविप की राष्ट्रीय मंत्री शालिनी वर्मा एवं लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर त्रिशताब्दी समारोह समिति की अखिल भारतीय सचिव माला ठाकुर की उपस्थिति में गत 13 नवंबर को महेश्वर (मालवा प्रांत) से हुआ। महेश्वर से आरंभ हुई यात्रा इंदौर, उज्जैन, भोपाल, विदिशा, रीवा, प्रयागराज, अयोध्या होते हुए गोरखपुर पहुंचेगी। इस दौरान मानवंदना यात्रा लगभग तेरह सौ किलोमीटर की दूरी तय करेगी। 'मानवंदना यात्रा' के रथ को अहिल्याबाई होल्कर की राजधानी महेश्वर का स्वरूप दिया गया है, जिसमें अहिल्याबाई की मूर्ति स्थापित की गई है। यात्रा के दौरान विभिन्न स्थलों पर संगोष्ठी, संवाद, प्रदर्शनी, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि का आयोजन भी होगा। 'मानवंदना रथ यात्रा' की संयोजक तथा अभाविप की मालवा प्रांत मंत्री राधिका सिकरवार ने कहा कि पुण्यश्लोक अहिल्याबाई का जीवन अनुकरणीय है। उनके जीवन से वर्तमान युवा पीढ़ी परिचित हो सके, इसी उद्देश्य को लेकर 'मानवंदना यात्रा' का आयोजन किया जा रहा है। इससे जनसामान्य को अहिल्याबाई के विशाल तथा प्रेरणादायक व्यक्तित्व से परिचित होने का अवसर मिलेगा। ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

भारत ने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी-एशिया रैंकिंग में मारी बाजी

क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी-एशिया-2025 रैंकिंग में भारत ने अपना वर्चस्व स्थापित किया है। अकादमिक और शोध संबंधी उत्कृष्टता, नवाचार और अंतरराष्ट्रीयकरण में विशिष्ट प्रदर्शन करने वाले शीर्ष संस्थानों की रैंकिंग ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भारत के तेजी से बढ़ते प्रभाव को सामने रखा है। भारत के दो संस्थान क्यूएस एशिया रैंकिंग-2025 के शीर्ष-50 में और सात संस्थान शीर्ष-100 में शामिल हैं। इसमें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (दिल्ली) 44वें स्थान पर है। भारतीय संस्थानों में सबसे महत्वपूर्ण सुधार यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज (यूपीईएस) ने हासिल किया है। यह संस्थान 70 पायदान ऊपर चढ़कर 148वें स्थान पर पहुंच गया है। यह रैंकिंग पूर्वी, दक्षिणी, दक्षिण-पूर्वी और मध्य एशिया के 25 देशों को कवर करने वाले 984 संस्थानों का मूल्यांकन करती है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी एशिया-2025 रैंकिंग, संस्थानों और छात्रों को अपने क्षेत्र के भीतर संस्थागत प्रदर्शन पर सीधी तुलना करने की सुविधा प्रदान करती है। नवीनतम रैंकिंग में भारत के सबसे अधिक संस्थान हैं, जो उभरते और अच्छी तरह से स्थापित दोनों तरह के विश्वविद्यालयों की विविधता को प्रदर्शित करता है।

भारत दक्षिणी एशिया के शीर्ष दस विश्वविद्यालयों में अपना वर्चस्व रखता है, जिसमें सात संस्थान इस सूची में शामिल हैं। शीर्ष 50 में भारत के दो संस्थान- आईआईटी दिल्ली (44) और आईआईटी बंबई (48) शामिल हैं। इसी तरह शीर्ष-100 में आईआईटी मद्रास (56), आईआईटी खड़गपुर (60), भारतीय विज्ञान संस्थान (62), आईआईटी कानपुर (67) और दिल्ली विश्वविद्यालय (81) सहित पांच संस्थान भारत के सशक्त शैक्षिक परिदृश्य को प्रदर्शित करते हैं। शीर्ष 150 में आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी रुड़की, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय (120), यूपीईएस (148) और वेल्लोर प्रौद्योगिकी संस्थान (150) जैसे संस्थान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की गहराई को सामने रखते हैं।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली (आईआईटीडी) ने भारत के लिए सर्वोच्च रैंकिंग हासिल की है, जो पिछले वर्ष के 46वें स्थान से 44वें स्थान पर पहुंच गया है, जिसमें 99 प्रतिशत का प्रभावोत्पादक एंपलॉयर रेपुटेशन स्कोर है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे (आईआईटीबी) 48वें स्थान पर है। दिल्ली विश्वविद्यालय ने अपनी रैंकिंग में सुधार किया है, जो 94वें से 81वें स्थान पर पहुंच गया है। इसी प्रकार अन्ना विश्वविद्यालय ने उच्च रिसर्च आउटपुट पर जोर देते हुए प्रति फैकेल्टी पेपर इंडिकेटर में 100 का पूर्ण स्कोर प्राप्त किया। 15 विश्वविद्यालयों ने पीएचडी स्टाफ इंडिकेटर में 99 प्रतिशत से अधिक स्कोर प्राप्त किया, जबकि नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी और कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बेंगलुरु ने फैकल्टी-स्टूडेंट इंडिकेटर में 100 का पूर्ण स्कोर प्राप्त किया। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग-2025 में भारत के 46 संस्थान शामिल हैं, जबकि इससे पहले 2015 में सिर्फ 11 संस्थान थे। यह उपलब्धि वैश्विक स्तर पर शिक्षा क्षेत्र की महाशक्तियों के बीच भारत को एक दुर्जेय प्रतियोगी के रूप में स्थापित करती है। ■

भारत के दो संस्थान क्यूएस एशिया रैंकिंग-2025 के शीर्ष-50 में और सात संस्थान शीर्ष-100 में शामिल हैं। इसमें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (दिल्ली) 44वें स्थान पर है। भारतीय संस्थानों में सबसे महत्वपूर्ण सुधार यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज (यूपीईएस) ने हासिल किया है।

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर

■ डा. रविन्द्र प्रताप सिंह

भारत प्राचीनकाल से ही महान महिलाओं की धरती रही है। अनेकानेक महिलाओं ने भारत के इतिहास में स्वर्णिम स्थान अर्जित किया है। ऐसे ही महान विभूतियों में शामिल अहिल्याबाई होल्कर का व्यक्तित्व एवं कृतित्व उन्हें विश्व की श्रेष्ठतम महिलाओं की पंक्ति में अग्रणी बनाता है। भारत के इतिहास और जनमानस पर उनका विशेष प्रभाव रहा है। अहमदनगर के जामखेड़ के चौड़ी ग्राम में जन्मी एक छोटी सी बालिका आगे चलकर भारत के आभामंडल पर एक इतनी बड़ी व्यक्तित्व के रूप में उभर कर आएगी? यह किसी को नहीं पता था।

इंदौर राज्य के मल्हारराव की पुत्रवधू अहिल्याबाई की ख्याति न केवल भारत में, बल्कि पश्चिमी इतिहासकारों एवं विद्वानों के लिए भी अध्ययन का विषय रहा है। 1732 में मालवा (वर्तमान में मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग) में मराठा राज्य का आगमन हुआ और इस प्रकार होल्कर, सिंधिया एवं पवार वंशों के मराठा राज्य मालवा में शामिल हुए। 1734 में मालवा में होल्कर राज्य की विधिवत स्थापना हुई। होल्कर वंश में 14 शासक हुए और 220 वर्ष तक मालवा में होल्कर राज्य रहा। 16 जून 1948 को होल्कर राज्य का विलय भारतीय संघ में हो गया। इस वंश की अहिल्याबाई की कीर्ति पूरे भारत

में फैली। होल्करों के पूर्वज महाराष्ट्र में वाफ गांव के मूल निवासी थे। कुछ समय बाद इनके वंशज पुणे के पास होल नाम के गांव में बस गए। होल के निवासी होने के कारण इनका उपनाम 'होल्कर' पड़ा।

होल्कर वंश की अहिल्याबाई में विवेक, नम्रता, सेवा, त्याग और सहनशीलता तो थी ही, लेकिन जाटों और मराठों के बीच घमासान युद्ध में उनके पति खंडेराव की मृत्यु हो गई। इसके बाद अहिल्याबाई ने सती होने का प्रण लिया कि प्राणों से प्रिय पति अगर जीवित नहीं हैं तो मेरे जीवन का भी कोई अर्थ नहीं है। लेकिन ससुर मल्हार राव के समझाने के बाद अहिल्या ने सती होने का विचार त्यागा और प्राणपन से प्रजा की सेवा करने का दायित्व निभाया। 'बहुजन हिताय-बहुजन सुखाय' के मूल मंत्र को अपने जीवन

'बहुजन हिताय-बहुजन सुखाय' के मूल मंत्र को अपने जीवन में उतार राजसी सुखों का त्याग कर दुखी, पीड़ित जन की सेवा को ही उन्होंने अपने जीवन का परम लक्ष्य बना लिया। कुशल शिक्षक मल्हार राव के संरक्षण एवं मार्ग निर्देशन में अहिल्याबाई ने राजकाज में प्रशिक्षण प्राप्त किया।

में उतार राजसी सुखों का त्याग कर दुखी, पीड़ित जन की सेवा को ही उन्होंने अपने जीवन का परम लक्ष्य बना लिया।

कुशल शिक्षक मल्हार राव के संरक्षण एवं मार्ग निर्देशन में अहिल्याबाई ने राजकाज में कुशल प्रशिक्षण प्राप्त किया। स्वयं मल्हार राव अपने जीवित रहते ही पुत्रवधू अहिल्या को देश-दुनिया की भौगोलिक, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति से परिचित कराना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अहिल्या को देशाटन के लिए भी भेजा ताकि वह समाज के बीच में रहकर ही समाज का बेहतर ज्ञान प्राप्त कर सकें। इसका परिणाम यह हुआ कि अहिल्याबाई स्वयं लगान वसूलनें, न्याय करने, आदेश निकालने और जनता के दुख-दर्द को दूर करने का हर संभव प्रयास करनें में संलग्न हो गई।

मल्हार राव अक्सर युद्धों में व्यस्त होने के कारण राज्य से जब वह बाहर रहते तो पत्रों के माध्यम से अहिल्याबाई का मार्गदर्शन भी करते थे। डा. सुनीता शर्मा ने मल्हार राव के एक पत्र का उल्लेख किया है जिसे मल्हार राव ने 3 जनवरी 1765 को आगरा से अहिल्याबाई को लिखा था, 'मैंने पिछले पत्र में भी तुम्हें लिखा था कि बिना रुके सीधे ग्वालियर पहुंचो। वहां पांच-सात दिन ठहरो। वहां एक हजार या पांच सौ बड़ी तोपों के गोले और हो सके तो इतनी ही छोटी बंदूकों के गोले तैयार कराओ। पसंद करके सौ बड़े बर्तन खरीदो, जिनमें तीरों के लिए एक सेर का पाउडर समा सके। इस काम को तुरंत करो। मैंने तुम्हें पूर्व में भी छोटी तोपों की ओर ध्यान देने को कहा था। हथियार बनाने के लिए एक माह के खर्च की पूरी व्यवस्था रखो।'

यह पत्र यह दर्शाता है कि मल्हार राव का अहिल्याबाई की कार्यकुशलता और राजकाज में उनकी निपुणता कितना विश्वास था। होल्कर राज्य के संस्थापक, मराठा साम्राज्य के भीष्म पितामह मल्हार राव का 1766 में निधन हो गया। मराठा साम्राज्य के आधार स्तंभों में से एक पराक्रमी, शक्तिशाली और स्वामी भक्त सरदार मल्हार राव के जाने से मराठा साम्राज्य को भी गहरा आघात लगा। एक के बाद एक अपने प्रिय परिजनों, पहले पति और अब पिता तुल्य ससुर का निधन अहिल्याबाई के लिए असहनीय था। मात्र 21 वर्ष की आयु में मालेराव (सुपुत्र अहिल्याबाई) मालवा की गद्दी पर आसीन हुआ। अहिल्याबाई के लिए मां, पत्नी, बहू से बड़ा दायित्व था, अपनी प्रजा के हित के लिए कार्य करने का। इतिहास में शायद ही ऐसा कोई और उदाहरण देखने को मिलेगा।

मल्हार राव के निधन के बाद अहिल्याबाई के सुपुत्र मालेराव मालवा की गद्दी पर आसीन हुए लेकिन दुर्भाग्य से उनका भी असामयिक निधन हो गया, जिससे राज्य में चोर, डाकुओं का आतंक इतना अधिक बढ़ गया था कि व्यापारी, यात्री और प्रजा, सभी भयभीत थे। ऐसे में रानी अहिल्याबाई ने घोषणा की कि जो भी व्यक्ति इन डाकुओं का राज्य से सफाया कर देगा, उससे वह अपनी पुत्री का विवाह कर देंगी। यशवंत राव फणसे ने रानी की शर्त पूरा किया और राज्य से चोर, डाकुओं का सफाया कर दिया। इस तरह मुक्ताबाई का विवाह

वीर एवं बुद्धिमान योद्धा यशवंत से हुआ। मुक्ताबाई के पुत्र नथ्या से अहिल्याबाई अत्यंत प्रेम करती थीं। किन्तु दुर्भाग्य से एक लंबी बीमारी से नथ्या की मृत्यु हो गई और उसके पश्चात यशवंत राव फणसे की असामयिक मृत्यु ने अहिल्याबाई को तोड़कर रख दिया। दुर्भाग्य तो यह रहा कि पति की मृत्यु पर पुत्री मुक्ताबाई ने भी सती होने का निश्चय किया। पहले पति, फिर ससुर, पुत्र, नवासा, दामाद और पुत्री के इस प्रकार निधन से अहिल्याबाई जीवन का आनंद जाता रहा क्योंकि धीरे-धीरे अपने सभी बिछड़ रहे थे। ऐसे आघातों को सहन करना किसी लौह महिला के लिए भी सहनीय नहीं होगा। जहां ऐसी कठिन परिस्थितियों में लोग अपना धैर्य और साहस खो देते हैं, वहीं अहिल्याबाई अपनी प्रजा के हित एवं संरक्षण के लिए उठ खड़ी हुईं। अपने साम्राज्य के संरक्षण के लिए जो कुछ भी संभव था, वह उन्होंने किया।

अहिल्याबाई ने 1767 में होल्कर राज्य की बागडोर संभाली। ससुर मल्हार राव से मिले संस्कारों एवं मार्गदर्शन का यह प्रभाव रहा कि रानी अहिल्याबाई में एक कुशल शासक के सभी गुण विद्यमान थे। लेकिन मालवा राज्य का उत्तराधिकारी कौन बनेगा यह गंभीर प्रश्न खड़ा हो गया था? इसी कारण राज्य के अंदर के विद्रोही तत्व सर उठाने लगे, जिनमें से गंगोबा तात्या एक थे। गंगोबा तात्या ने पेशवा माधवराव के चाचा रघुनाथराव को महेश्वर (मालवा) पर आक्रमण करके उनको महेश्वर जीतने में मदद के लिए बुलाया, लेकिन अहिल्याबाई गंगोबा और रघुनाथ राव की इस चेष्टा से बिल्कुल अंजान थी। जैसे ही अहिल्याबाई को इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने होल्करों के विश्वासी सरदार महादजी शिंदे और तुकोजी होल्कर को मदद के लिए पत्र भेजा। महादजी और तुकोजी ने बिना समय नष्ट किए अपनी सेनाएं महेश्वर की तरफ मोड़ दीं और महेश्वर पहुंच गए। इस दौरान अहिल्याबाई ने भी रघुनाथराव को पत्र लिखकर कहा कि वह उनके राज्य से महिलाओं की ऐसी सेना तैयार करेंगी जो आखिरी सांस तक अपने राज्य की रक्षा के लिए तैयार रहेगी। ऐसी सेना से अगर आप हार गए तो वह आपके लिए सबसे लज्जास्पद बात होगी, बावजूद इसके रघुनाथराव महेश्वर पर आक्रमण करने के लिए क्षिप्रा नदी के किनारे आ पहुंचे। इस बीच उन्हें तुकोजी होल्कर से एक पत्र मिला जिसमें उन्होंने रघुनाथ राव को युद्ध के गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहने के लिए बोला। रघुनाथ राव इस एकता को देखकर घबरा गए और उन्होंने महेश्वर पर आक्रमण नहीं करने का फैसला लिया। अहिल्यादेवी की इस सफल कूटनीति से रघुनाथ राव बिना युद्ध किए वापस लौट गए। इस सफलता से अहिल्याबाई का कद और सम्मान और बढ़ गया।

जन कल्याण के क्षेत्र में भी रानी अहिल्याबाई ने अनेक कार्य किए। वह अपनी प्रजा को अपनी संतान मानती थीं। उन्होंने अपने शासनकाल में कई कानूनों को समाप्त किया, किसानों का लगान कम किया, कृषि, उद्योग धंधों को सुविधा देकर विकास

अहिल्याबाई ने स्त्रियों को उनका उचित स्थान दिया। नारी शक्ति का भरपूर उपयोग किया। उन्होंने बता दिया कि स्त्री किसी भी स्थिति में पुरुष से कम नहीं है। अपने शासनकाल में उन्होंने नदियों पर जो घाट स्नान आदि के लिए बनवाए थे, उनमें महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था भी हुआ करती थी। स्त्रियों के मान-सम्मान का बड़ा ध्यान रखा जाता था।

के अनेक काम किए। चोर, डाकुओं को सही रास्ते पर लाकर उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला उन्हें बसाया भी। काशी में एक ब्राह्मण का घर जलकर राख हो गया था। वह सहायता के लिए रानी के पास आया तो उन्होंने इस बात की सत्यता जानने पर उसे नया घर बनवा कर भेंट किया। अहिल्याबाई राहगीरों, गरीबों, दिव्यांगों, साधु-संतों, पशु-पक्षियों, जीव-जंतुओं सभी का ध्यान रखती थीं। यहां तक कि अपने सैनिकों, कर्मचारियों के कल्याण के लिए भी वह कभी पीछे नहीं हटीं। अहिल्याबाई का हृदय समाज के सभी वर्गों के लिए धड़कता था।

अहिल्याबाई ने स्त्रियों को उनका उचित स्थान दिया। नारी शक्ति का भरपूर उपयोग किया। उन्होंने

बता दिया कि स्त्री किसी भी स्थिति में पुरुष से कम नहीं है। अपने शासनकाल में उन्होंने नदियों पर जो घाट स्नान आदि के लिए बनवाए थे, उनमें महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था भी हुआ करती थी। स्त्रियों के मान-सम्मान का बड़ा ध्यान रखा जाता था। लड़कियों को पढ़ाने-लिखाने का जो घरों में थोड़ा-सा चलन था, उसे विस्तार दिया गया। दान-दक्षिणा देने में महिलाओं का वह विशेष ध्यान रखती थीं।

लगभग तीस वर्ष के शासनकाल के दौरान मराठा प्रांत की राजमाता अहिल्याबाई होल्कर ने एक छोटे से गांव इंदौर को एक समृद्ध एवं विकसित नगर बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी, द्वारका, पैठण, महेश्वर, वृंदावन, सुपलेश्वर, उज्जैन, पुष्कर, पंढरपुर, चिंचवाड़, चिखलदा, आलमपुर, देवप्रयाग, राजापुर आदि स्थानों पर मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाया तथा घाट बनवाए। अन्न सत्र या सदावर्त खुलवाए, जहां लोगों को प्रतिदिन भोजन मिलता था। काशी विश्वनाथ मंदिर के साथ-साथ पूरे देश के मंदिरों का निर्माण एवं पुनर्निर्माण का कार्य उन्होंने कराया। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में तीर्थ यात्रा के लिए विश्रामगृह, अयोध्या, नासिक में भगवान राम के मंदिरों का निर्माण, सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण, उज्जैन में चिंतामणि गणपति मंदिर निर्माण जैसे कार्य रानी ने दिल खोलकर किए। उन्होंने कल्याणकारी एवं परोपकारी कार्यों द्वारा राष्ट्र निर्माण का महत्ती कार्य भी किया तथा देश में धार्मिक, सामाजिक, राष्ट्रीय एकता कायम करने के लिए सराहनीय प्रयास किए। इन सभी कार्यों के लिए भी केवल 'खासगी संपत्ति' ही खर्च करती थीं, जिस पर पूर्णतया राज परिवार का अधिकार था। प्रसिद्ध इतिहासकार चिंतामणि विनायक वैद्य ने लिखा है, ''उनकी धार्मिकता इतनी उदार थी कि धर्म व नीति के हर क्षेत्र में उन्होंने अपना नाम अजर-अमर कर दिया। उनका दान-धर्म इतना महान था कि वैसा दान-धर्म आज तक हिंदुस्थान में किसी ने भी नहीं किया है।''

अहिल्याबाई का सादगीपूर्ण जीवन, नीति युक्त शासन और कुशल राजनीति का संसार के इतिहास में एक विशेष स्थान है। प्रजा के हित में उठाए कदमों ने उन्हें लोकमाता की उपाधि दी। 13 अगस्त 1795 के दिन 70 वर्षीया रानी की दिव्य आत्मा ने शरीर छोड़ दिया। रानी अहिल्याबाई में इतिहास के गौरवशाली वीरों के गुण देखने को मिलते हैं। यह एक आश्चर्य का विषय है कि कोई भी महिला इतनी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद सर्वगुण संपन्न कैसे हो सकती है? इतिहास, वर्तमान और भविष्य में केवल एक ही व्यक्ति में इतने गुणों का समावेश होना संभव ही नहीं है।

जवाहरलाल नेहरू नें अपनी कृति भारत एक खोज में लिखा है कि "मध्य भारत में, इंदौर की अहिल्याबाई का शासन, तीस वर्षों तक चला। यह एक ऐसे काल के रूप में प्रसिद्ध है, जिसके दौरान इंदौर में एक उत्तम व्यवस्था और अच्छी सरकार बनी तथा लोगों को समृद्धि प्राप्त हुई। वह एक बहुत ही योग्य शासक और प्रबंधक थीं, जिन्हें अपने जीवनकाल में बहुत सम्मान

अहिल्याबाई का सादगीपूर्ण जीवन, नीति युक्त शासन और कुशल राजनीति का संसार के इतिहास में एक विशेष स्थान है। प्रजा के हित में उठाए कदमों ने उन्हें लोकमाता की उपाधि दी। लगभग तीस वर्ष के शासनकाल के दौरान उन्होंने इंदौर को एक समृद्ध एवं विकसित नगर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

प्राप्त हुआ। उनकी मृत्यु के बाद, कृतज्ञ लोगों द्वारा उन्हें एक संत के रूप में माना गया।

कवयित्री जोआना बैली ने 1849 में बिल्कुल सही कहा था कि बाद के दिनों में ब्रह्मा के यहां से हमारी भूमि पर शासन करने आईं, एक श्रेष्ठ महिला, जो दयालु थी, जिनका हृदय उज्ज्वल था, जिनकी कीर्ति, सम्मानित नाम थी, उनका नाम अहिल्याबाई था। अपने धर्माचरण, शासन प्रबंध, विद्वानों का सम्मान एवं न्याय, दानशीलता, उदार धर्म नीति, भक्ति भावना, वीरता, त्याग एवं बलिदान, साहस, शौर्य से परिपूर्ण रानी अहिल्याबाई युगों- युगों तक अमर रहेंगी। इतिहास के दिग्गज शासकों के गुणों से परिपूर्ण रानी हम सभी की प्रेरणास्रोत हैं। रानी अहिल्याबाई का नाम सदा स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। ■

आदर्श राज व्यवस्था की प्रणेता

■ डा. रवि रमेश चंद्र शुक्ला

ग्रीक दार्शनिक प्लेटो का दार्शनिक राजा का सिद्धांत आदर्श राज्य का मुख्य आधार था। यह इस धारणा से व्युत्पन्न हुआ कि दार्शनिक के पास शासन करने के लिए ज्ञान, बुद्धि और प्रशिक्षण होता है। किसी अन्य कार्य के समान, शासन करने के लिए भी कौशल और योग्यताओं की आवश्यकता होती है क्योंकि उसका लक्ष्य सभी की सामान्य भलाई होता है। इन्हीं गुणों की प्रतिमूर्ति अहिल्याबाई होल्कर थीं। आज सारा विश्व उनकी 300वीं जन्म जयंती वर्ष मना रहा है। अहिल्याबाई होल्कर का जन्म 31 मई 1725 को महाराष्ट्र राज्य के चौंढी नामक गांव (जामखेड, अहमदनगर) में हुआ था। वह एक सामान्य किसान मानकोजी शिन्दे की पुत्री थी। औपचारिक शिक्षा सामान्य स्तर पर प्राप्त करके, स्वाध्याय और रुचि से उन्होंने अपार ज्ञान अर्जित किया था। अहिल्याबाई दस वर्ष की आयु में मालवा के होल्कर वंशीय राज्य के संस्थापक मल्हारराव होल्कर के पुत्र खण्डेराव के साथ परिणय सूत्र में बंध गई थीं।

अपनी कर्तव्यनिष्ठा से उन्होंने सास-ससुर, पति एवं अन्य सम्बन्धियों के हृदयों को जीत लिया। समयोपरांत एक पुत्र, एक पुत्री की माता बनीं। 29 वर्ष की आयु में पति का युद्ध क्षेत्र में तोप का गोला लगने से देहांत हो गया। 1766 में वीरवर ससुर मल्हारराव भी चल बसे। अहिल्याबाई होल्कर के जीवन से एक महान साया उठ गया। उसके बाद मालवा शासन की बागडोर उन्हें संभालनी पड़ी। कालांतर में देखते ही देखते पुत्र मालेराव, दोहित्र नत्थू, दामाद यशवंत फणसे, पुत्री मुक्ता भी अपनी माता को अकेला छोड़ कर चल बसी। दार्शनिक शासक महारानी अहिल्याबाई होल्कर 13 अगस्त 1795 को नर्मदा तट पर स्थित महेश्वर के किले में भारतीय इतिहास में अपना नाम स्वर्णाक्षरों में लिखाकर सदैव के लिए चिरनिंद्रा में सो गईं।

18वीं सदी में जब सारे विश्व में महिला अधिकारों के नाम पर स्त्रीवादी आंदोलनों की बहस छिड़ी थी, तो उस समय मालवा क्षेत्र पर होल्कर घराने का राज्य अपनी महान शासक अहिल्याबाई होल्कर की छत्रछाया में राजधर्म का मार्ग प्रशस्त कर रहा था। पश्चिम में सबसे सशक्त लोकतंत्र होने के बावजूद महिलाओं को दोयम दर्जे का स्थान मिलता रहा। उसके विपरीत भारत में हिंदू राज व्यवस्था

को संकल्पना से प्रेरित मालवा राज्य में अहिल्याबाई होल्कर धर्म को धुरी पर आधारित आदर्श राज्य को स्थापना कर चुकी थीं। मध्यकालीन भारत मुगलों, आदिलशाही और अन्य राजाओं की विलासिता, क्रूरता और प्रजा के दमन का साक्षी बना। किंतु उसी अंधकार में आशा और शौर्य का दैदीप्यमान तारा अहिल्याबाई होल्कर के रूप में क्षितिज पर चमकता है। एक अलिप्त शासक के रूप में धर्मशास्त्रों के बताए मार्ग पर चलकर वह इतिहास में अमर हो गईं। उनकी प्रजा उन्हें देवी और माता की तरह मानती थी।

लगभग तीस वर्षों के शासन काल में अहिल्याबाई ने संपूर्ण भारत वर्ष में धर्म ध्वजा आरोहण किया। साथ ही अपने राज्य की भौगोलिक सीमाओं की सूझबूझ से रक्षा की। राजकाज, युद्धनीति, प्रजा वात्सल्य की गुण उनमें पहले से विद्यमान थे। उनके ससुर मल्हारराव होल्कर ने उन्हें पर्याप्त अवसर देकर विकसित किया। इतिहासकार बी. पी. सिन्हा के अनुसार मालवा प्रदेश पश्चिम में चंबल नदी से लेकर पूर्व में एरण तक, दक्षिण में विंध्य श्रेणी से लेकर उत्तर में चंबल के उत्तरी मोड़ तक विस्तृत था।

अहिल्याबाई होल्कर का संपूर्ण व्यक्तित्व अद्भुत गुणों का उच्चांक था। एक पुत्री और पुत्रवधू के रूप में पिता और ससुराल का यशवर्धन किया। एक गृहणी के रूप में बड़े और संयुक्त कुटुम्ब को संभाला। धर्मपरायण हिन्दू के रूप में गंगासागर से रामेश्वरम तक, सोमनाथ से जगन्नाथ तक अनेकों मंदिर का निर्माण कराया। कई मंदिरों का जीणोद्धार और पुनर्निर्माण कराया। मुस्लिम धर्मांध मुगल औरंगजेब द्वारा तोड़े गए काशी विश्वनाथ मंदिर को 111 साल बाद फिर से प्राण-प्रतिष्ठित किया। अनेकों सड़कों, धर्मशालाओं, यज्ञस्थलों का निर्माण करने के साथ ही उन्हें दान दिया। लड़कियों की आधुनिक शिक्षा की जननी के रूप में स्कूल बनवाए। विधवा महिलाओं को संपत्ति का अधिकार दिया। जनसुलभ प्रशासन और कठोर न्याय व्यवस्था से जनता के लिए लोकमाता का रूप बन गईं थीं। सात बारह, सिंचाई व्यवस्था जैसी किसान कल्याण की योजनाएं चलाई। महेश्वर में साड़ियों और अन्य उद्योग धंधों की नगरी बसाया। इंदौर को छोटे से गांव से एक आधुनिक नगर बनाया।

अहिल्याबाई होल्कर भारत के इतिहास में एक प्रजावत्सल्य शासक के साथ-साथ एक महान रणनीतिकार, योद्धा और राजनीतिज्ञ के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। अहिल्याबाई ने अपने पड़ोसी राज्यों के साथ मजबूत संबंध बनाए। उन्होंने कई छोटे राजाओं और सामंतों के साथ गठबंधन किया, जिससे उनकी सेना को मजबूती मिली। सेना के लिए आधुनिक

अहिल्याबाई होल्कर भारत के इतिहास में प्रजावत्सल्य शासक के साथ-साथ एक महान रणनीतिकार, योद्धा और राजनीतिज्ञ के रूप में प्रसिद्ध हैं। अहिल्याबाई ने अपने पड़ोसी राज्यों के साथ मजबूत संबंध बनाए। उन्होंने अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए किले और गढ़ों का निर्माण किया, जिससे दुश्मनों के हमलों को रोका जा सका।

युद्ध सामग्री के लिए नई तकनीक और अस्त्र-शस्त्रों का उपयोग किया, जिससे उनकी सेना की क्षमता में वृद्धि हुई। उन्होंने अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए किले और गढ़ों का निर्माण किया, जिससे दुश्मनों के हमलों को रोका जा सका। राजमाता ने अस्त्र-शस्त्र से सुसज्जित होकर कई बार युद्ध में अपनी सेना का नेतृत्व खुद किया था। गोहाड का क़िला जीतकर उन्होंने युद्ध में अपनी प्रथम जीत दर्ज की। उनकी धार्मिकता के बाद जनता ने उनकी वीरता भी देखी। वह एक साहसी योद्धा और बेहतरीन तीरंदाज के रूप में घोड़े और हाथी पर सवार होकर युद्ध करती थीं। एक और जहां राज्य को चोर डाकुओं से सुरक्षित रखा, वहीं दूसरी ओर राज्य के शत्रुओं (उदयपुर के राजा जगत सिंह और रामपुरा के सरदार चंद्रावत माधव सिंह, गंगाधर चंद्रचूड़, दादा राघोबा) का भी दमन किया।

वह एक कुशल रणनीतिकार भी थीं। एक बार जब उनकी सत्ता छीनने के इरादे से राघोबा

दादा पेशवा की सेना लेकर उज्जैन तक गए थे। देवी अहिल्याबाई ने बिना घबराए बहुत ही सटीक साहसिक कदम उठाया। अहिल्याबाई ने महिलाओं की सेना भी तैयार कर उन्हें हथियार चलाना, रण व्यूह का प्रशिक्षण देना भी प्रारंभ किया। रानी ने अपने शत्रु दादा राघोबा को एक पत्र में लिखा कि आप मेरा राज्य हड़पने आए हैं। यह आपको शोभा नहीं देता। आप एक नारी के साथ युद्ध मत कीजिए, नहीं तो यह कलंक मिट नहीं पाएगा। मैं एक असहाय नारी हूं। यह समझकर आप आए हैं, तो इस बात का पता युद्ध भूमि में चलेगा। मैं एक स्त्री हूं। युद्ध में हार भी गई तो मुझे कोई याद नहीं रखेगा, आप युद्ध में हार

रणनीतियों ने अहिल्याबाई को एक कुशल शासक और सैन्य नेता के रूप में स्थापित किया। यह छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्श हिंदवी स्वराज्य का साकार रूप था। उनमें माता जीजाबाई के ममता, करुणा, दूरदर्शिता के साथ ही, छत्रपति शिवाजी महाराज जैसी वीरता, चतुराई और निडरता थी।

गए तो जग में अब आपकी हंसी होगी। मैं अपनी महिला सेना के साथ युद्ध भूमि में आपका मुकाबला करूंगी। आपका भला इसी में है, जैसे आए हैं, वैसे ही चुपचाप वापस चले जाएं।

दादा राघोबा ने जब यह पत्र पढ़ा तो विशाल सेना, महिला सेना और युद्ध की तैयारी ने दादा राघोबा के हौसले पस्त कर दिए और इस तरह रानी ने बिना युद्ध लड़े, बिना खून-खराबे के युद्ध जीता भी और एक शत्रु को अपने व्यवहार से मित्र भी बना लिया। आंतरिक और वाह्य विद्रोह रोकने के लिए अहिल्याबाई ने स्थानीय समुदायों को अपनी सेना में शामिल किया और स्थानीय सेनापतियों को प्रोत्साहित किया। हमेशा आक्रमण करने को तत्पर भील और गोंड विद्रोहियों से उन्होंने कई वर्षों तक अपने राज्य को सुरक्षित रखा। अपनी पुत्री का विवाह यशवंत फणसे नामक जनजातीय योद्धा युवक से कराया, जिससे उन्हें क्षेत्र में भौगोलिक और रणनीतिक लाभ मिला।

राजमाता की शासन व्यवस्था का सबसे बड़ा बदलाव था सेना को राज्य से अलग करना। सेना की व्यवस्था और उसमें व्यावसायिक दृष्टिकोण लाने के लिए उसे राज्य के बाकी प्रशासन से अलग किया। सैन्य और सुरक्षा के विषय अपने विश्वासपात्र सूबेदार तुकोजीराव होल्कर को सौंपा था। सेनापति के रूप में तुकोजी एक अभेद्य दीवार की तरह राज्य की रक्षा करते रहे। वहीं राजमाता ने धर्म, प्रशासन और लोक कल्याण की जिम्मेदारी खुद के पास रखा। उनका निजी जीवन एक संन्यासिन का था। राज्य के कोष को वह जनता की निधि मानती थीं। इसलिए अपने व्यक्तिगत खर्च को भी राज्य के व्यय से अलग किया। वह अपना खर्च अपने संचित धन से करती थी और राज्य के लिए खर्च राजकोष से आता था। वास्तव में शासन व्यवस्था में उन्होंने एक अलग स्तर की पारदर्शिता को स्थापित किया। न्याय और प्रशासन को मजबूत किया, जिससे उनके राज्य में स्थिरता बनी रही और विद्रोहों को दबाया जा सका।

उनकी रणनीतियों ने उन्हें एक कुशल शासक और सैन्य नेता के रूप में स्थापित किया। यह छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्श हिंदवी स्वराज्य का साकार रूप था। उनमें माता जीजाबाई के ममता, करुणा, दूरदर्शिता के साथ ही, छत्रपति शिवाजी महाराज जैसी वीरता, चतुराई और निडरता थी। इसीलिए उन्हें युधिष्ठिर, कौटिल्य, विदुर जैसे मनीषियों की श्रेणी में शामिल किया गया है। उनका शासन काल एक हजार वर्ष पूर्व के सनातन भारत की झांकी थी। वह 70 वर्ष के जीवनकाल में इतना सब कुछ कर पाने वाली विश्व के महानतम शासकों की अग्रिम पंक्ति में स्थान पाती हैं। आज तीन सौ वर्ष बाद भी उनका स्वर्णिम इतिहास वामपंथी और कांग्रेसी साजिश की का शिकार होकर उपेक्षित था। लेकिन अब एक बार फिर से संपूर्ण भारतीय समाज को अपनी पुण्यश्लोक दार्शनिक शासक महारानी अहिल्याबाई होल्कर से प्रेरणा लेकर आदर्श समाज और राष्ट्र निर्माण के लिए आगे आना ही होगा। ■

साहित्य एवं कला को प्रोत्साहन

■ डा. अमित कुमार शर्मा

साहित्य मनुष्य को सुसंस्कृत बनाता है। 18वीं सदी में जन्मी अहिल्याबाई ने इस कथन को अपने जीवन से नए अर्थ प्रदान किए। अहिल्याबाई का पूरा जीवन समाज एवं व्यक्ति के लौकिक उन्नति और पारलौकिक कल्याण की कामना के प्रति समर्पित था। उन्होंने न सिर्फ अपने व्यक्तिगत जीवन को समाज के लिए आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया, बल्कि तत्कालीन समाज व्यवस्था को अपने आचरण और अविरल दृढ़ श्रद्धा से सुदृढ़ किया। उनका जीवन धर्म, राजनीति, संस्कृति और साहित्य इन चारों का विस्तार है। इसमें से किसी एक को भी हटाया नहीं जा सकता। अहिल्याबाई के जीवन का प्रत्येक क्षण और प्रत्येक कर्म समाज और राष्ट्र को समर्पित रहा। अतएव वह पूर्ण रीति से महाभारत के स्त्री पर्व के वाक्य का पालन अपने जीवन में करती थी-

"यतः कृष्णस्ततो धर्मो मतों धर्मस्ततो जयः"

शैव मत को मानने वाली अहिल्याबाई शिव की बड़ी भक्त थी। उन्होंने भारत के अनेक राज्यों के प्रसिद्ध मंदिरों का जीर्णोद्धार एवं निर्माण कराया था। गाय, ब्राह्मण एवं तुलसी की वह बड़ी भक्त थीं। प्रत्येक दिन गायों को उनकी ओर से चारा-पानी दिया जाता था। साथ ही विद्वानों और कर्मकांडी ब्राह्मणों को उनके पूजा कार्यों के अनुसार दक्षिणा देती थी। सर्वदा पुण्य के कर्मों में श्रद्धा रखकर भगवत भक्ति में प्रसन्न रहा करती थी। यही कारण है कि अहिल्याबाई होल्कर के विचार शुद्ध एवं सरल रहा करते थे। रामचरित मानस में गोस्वामी तुलसीदास कहते भी हैं-

काम, क्रोध, मद, लोभ, सब, नाथ नरक कर पंथ।
सब परिहरि रघुवीरहि, भजहुं भजहि जेहि संत।।
सगुण उपासक परमहित, निरत नीति दृढ़ नेम।
ते नर प्रान समान मम , जिनके द्विज पद प्रेम।।

अर्थात-वेद शास्त्र आदि ऐसा कहते हैं कि काम, क्रोध, मद, और लोभ यह सब नरक के मार्ग हैं। इस कारण इन्हें छोड़कर श्रीरामचंद्र के चरणों की सेवा करो। जो मनुष्य सगुन उपासना करते हैं, जो बड़े हितकारी हैं, जो नीति में निरत है, नियम में दृढ़ है और जिनकी ब्राह्मणों के चरण कमल में प्रीति है, वह मनुष्य मुझको प्राणों के समान प्यारे लगते हैं। इन्हीं उपरोक्त उपदेशों को ध्यान में रखते हुए अहिल्याबाई सदा अपने राज्य में ब्राह्मण, विद्वान, साहित्यकार, कवि, लेखक को उच्च स्थान दिया करती थी। इसलिए उनका जीवन इतना महान सार्थक एवं अनुकरणीय बन सका।

सच्चे अर्थों में अहिल्याबाई होल्कर का जो जीवन चरित्र दिखाई पड़ता है, उसमें साहित्य, कला और भारतीय संस्कृति का पग-पग पर संबंध दिखाई देता है। साहित्य मनुष्य को मधुमय बनाता है। यह बात अहिल्याबाई होल्कर बखूबी जानती थी। यही कारण है कि अपने शासन व्यवस्था में मानव समाज के स्वास्थ्य, विकास, सुखमय जीवन एवं सर्वांगीण प्रगति के लिए साहित्य एवं कला को आश्रय और प्रोत्साहन देने का महान कार्य किया। किसी भी देश या राज्य की साहित्य और कला वहां के राजा पर निर्भर करती है। अनादि काल से भारतीय संस्कृति में कला और साहित्य के संरक्षण का दायित्व राजा का एक कर्तव्य माना गया

है। इतिहास में ऐसे राजा भी हुए, जिन्होंने स्वयं साहित्य एवं कला की साधना की। संपूर्ण संस्कृत साहित्य राज्य संरक्षण में ही लिखा गया। कालिदास से लेकर बिहारी, भूषण, सेनापति आदि कवियों ने राज्य संरक्षण में रहते हुए ग्रंथों की रचना की। इसी तरह अहिल्याबाई होल्कर के शासनकाल में भी साहित्य और कला को एक नई ऊंचाई प्राप्त हुई।

वैसे तो अहिल्याबाई होल्कर को पुस्तकीय शिक्षा कम प्राप्त हुई थी, किंतु मराठी, संस्कृत, हिंदी और मोड़ी भाषा लिखना-पढ़ना जानती थी। बचपन से ही धार्मिक ग्रंथों का नियमित पाठ उनके जीवन का अंग था। यही कारण है कि अधिक पढ़ी-लिखी न होने के बावजूद साहित्य एवं कला की बौद्धिक विकास उच्च कोटि का था। उनके द्वारा समय-समय पर विभिन्न व्यक्तियों के लिखे गए पत्रों से पता चलता है कि उनकी भाषा-शैली और अर्थ-प्रसंग की छवि असाधारण थी। उनके पत्र व्यवहार से कई राज्य एक-दूसरे के निकट आ चुके थे। अहिल्याबाई का पत्र व्यवहार सारे भारतवर्ष में फैला हुआ था और यह कार्य उन ब्राह्मणों द्वारा होता था जो उनके आश्रय और अद्वितीय उदारता के प्रतिनिधि थे। उनके पत्रों में भाषा की गंभीरता उनके उदार व्यक्तित्व, राजनीतिक और कूटनीतिक प्रभाव एवं साहित्यिक शक्ति को दर्शाती है।

अहिल्याबाई होल्कर ने अपने राज्य में साहित्य-कला के संरक्षण एवं प्रोत्साहन के लिए विशेष व्यवस्था की थी। यही कारण है कि देश के कोने-कोने से अनेक कवि, विद्वान, साहित्यकार एवं कलाकार उनके राज्य में यश, कीर्ति और धन को प्राप्त कर रहे थे।

मध्यकालीन भारतीय साहित्य में एक ओर जहां कवि और विद्वान राज दरबारों में रहकर राजा के गुणों को बढ़ा-चढ़ा कर साहित्य की रचना कर रहे थे और विभिन्न राजा भी उन विद्वानों तथा कवियों को अपने दरबारों में महारत्न आदि उपाधियों और सुविधाओं से सुशोभित कर रहे थे। इसी समय रीतिबद्ध कवि मतिराम लिख रहे थे-

कुंदन को रंग फीको लगै, झलके अति अंगिनि चारु गोराई।

आंखिन में अलसानि, चितौन में मंजु विलासन की सरसाई।।

रीतिकाल के दौर में श्रृंगारिक वर्णन और चमत्कार प्रदर्शन की प्रधानता थी। नायिका भेद आदि काव्यांगों का प्रभाव लगभग सभी कवियों की लेखनी का प्रमुख विषय था और अश्लीलता के अंश भी मौजूद रहे। उदाहरण के लिए "कैलि कै राति अघाने नहीं दिन ही में लला पुनि घात लगाई।" दूसरी ओर वीर कवि भूषण वीरतापरक काव्य रचते हुए अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन कर रहे थे। किन्तु यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि शिवाजी और छत्रसाल के पराक्रम का वर्णन करते हुए उन्होंने हिन्दू जनता में आत्मविश्वास की लहर पैदा की –

"इंद्रा जिमि जंभ पर, बाडव सु अम्भ पर,
रावन संदभ पर रघुकुल राज है"।

इसके विपरीत अहिल्याबाई होल्कर अपने बारे में किसी भी प्रकार के अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन को न ही महत्व देती थी और न ही साहित्य में जगह देती थी। उन्होंने साहित्य को समाज से जोड़ा। इस विषय में एक प्रसंग प्रसिद्ध है कि एक समय एक ब्राह्मण ने अहिल्याबाई के संपूर्ण सद्गुणों का वर्णन करते हुए एक पुस्तक की रचना की और उस पुस्तक को उनके सम्मुख भेंट स्वरूप प्रस्तुत की। अहिल्याबाई ने उस पुस्तक को बड़ी सावधानी और सचेत होकर सुना और उसे सत्कार स्वरुप धन्यवाद दे कर कहा कि "तुमने मुझ सरीखी दीन पामर की व्यर्थ स्तुति क्यों की, मैं बड़ी पापिनी हूं। मैं इस योग्य नहीं हूं कि मेरी इस प्रकार स्तुति की जाए। इसकी अपेक्षा यदि तुम अपना अमूल्य समय परमात्मा की स्तुति में लगाते तो रचना कर्म का समय अवश्य सार्थक होता और उसकी पूर्ण भी तुमको आवश्यक होता।" ऐसा कहकर उन्होंने उस पुस्तक को नर्मदा नदी में बहा दिया और उस ब्राह्मण को ससम्मान यथा दान देकर शीघ्र विदा कर दिया।

अहिल्याबाई होल्कर ने अपने राज्य में साहित्य-कला के संरक्षण एवं प्रोत्साहन के लिए विशेष व्यवस्था की थी। यही कारण है कि देश के कोने-कोने से अनेक

कवि, विद्वान, ब्राह्मण, साहित्यकार एवं कलाकार उनके राज्य में यश, कीर्ति और धन को प्राप्त कर रहे थे।

कला एवं साहित्य के प्रति अहिल्याबाई होल्कर का समर्पण देखकर अधिकाधिक कलाकार उनके राज्य में आया करते थे। इन्हीं कलाकारों में एक अनंतफंदी जो एक यजुर्वेदी ब्राह्मण था, संगमनेर में रहता था। उसने अहिल्याबाई के राज्य में जाकर उनके सामने खेल, तमाशा एवं लावणी को प्रदर्शित करने का निश्चय किया। महेश्वर पहुंचकर अनंतफंदी ने अपने साथियों के साथ अहिल्याबाई होल्कर के सामने उत्तम से उत्तम और अनोखी लावनियां प्रस्तुत कीं। अहिल्याबाई ने कलाकार की कला को बड़े ध्यानपूर्वक देखा और सुना।

अहिल्या बाई ने अपने राज्य में धर्मशास्त्र, कर्मकांड, वेद, वेदांत, साहित्य, व्याकरण, पूजन एवं कीर्तन, ज्योतिष, वैद्यक आदि विद्याओं के प्रसिद्ध विद्वानों को देशभर से आमंत्रित कर महेश्वर में संरक्षण प्रदान किया। मराठी के सुप्रसिद्ध कवि मोरोपन्त भी उनकी कीर्ति सुनकर महेश्वर आए थे। मोरोपन्त मराठी के प्रसिद्ध कवि एवं भक्त थे।

उसके उपरांत कलाकार को अपने पास उपस्थित होने की आज्ञा दी। अहिल्याबाई ने कलाकार को सही मार्ग दिखलाते हुए कहा कि "तुम ब्राह्मण और कवि होकर अपना जीवन और कविता इस प्रकार क्यों नष्ट कर रहे हो। इसकी अपेक्षा यदि तुम स्वार्थ और परमार्थ दोनों बनाओ तो तुम्हारा तथा दूसरे लोगों का बड़ा हित हो।"

उनकी कही हुई बातें उस कलाकार को इस प्रकार घर कर गई कि उसने तय किया कि आज के बाद से अपना खेल एवं लावणी को हास्य-व्यंग्य के स्थान पर भक्ति की ओर मोड़ दूंगा। उसने यह भी तय किया कि अब घूम-घूम कर इस प्रकार से अपनी योग्यता का अपमान नहीं कराना है क्योंकि वह कलाकार बहुत प्रसिद्ध था और अपने क्षेत्र में प्रख्यात था। विशेष आग्रह पर ही उसने फिर अपनी लावणी और खेल को दिखाने का निश्चय किया। यह संयोग ही है कि अहिल्याबाई होल्कर उसी रास्ते से पुणे की तरफ जा रही थी कि बड़ी संख्या में भीड़ को देखकर उन्होंने जानना चाहा कि इतनी भीड़ क्यों है? सैनिकों द्वारा पता करने पर उन्हें पता चला कि श्रावण मास में आया हुआ अनंतफंदी नामक कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन कर रहा है। अहिल्याबाई ने अपनी पालकी को उस स्थान की तरफ ले जाने का आदेश दिया। जैसे ही अनंतफंदी को यह पता चला की अहिल्याबाई आ रही हैं तो उसने बड़ी ही प्रसन्नता से इस पद को गाकर और साथ ही भाव विभोर होकर नृत्य किया -

"मुख मुरली मनमोहन मूरत, देखत नैन निरावत हैं।
ग्वाल बाल संग वृंदावन ते, वेणु बजावत आवत हैं।।
नटवर भेष अलौकिक शोभा, कोटिन मदन लजावत हैं।
निरखि निरखि बलवंत श्याम छबि, रैन दिना मुख पावत हैं।।

यह महत्वपूर्ण घटना है कि अहिल्याबाई ने एक कलाकार को अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन से मुक्त कर वास्तविक जीवन से जोड़ते हुए भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपने दरबार में कवियों एवं कलाकारों को दरबारीपन के चारदीवारी से बाहर निकालकर उन्हें जीवन की वास्तविकता से न सिर्फ परिचय कराया, बल्कि भक्ति, नीति और सामाजिक सरकारों के मार्ग से आम जनमानस से भी जोड़ दिया।

उन्होंने अपने राज्य में धर्मशास्त्र, कर्मकांड, वेद, वेदांत, साहित्य, व्याकरण, पूजन एवं कीर्तन, ज्योतिष, वैद्यक आदि विद्याओं के प्रसिद्ध विद्वानों को देशभर से आमंत्रित कर महेश्वर में संरक्षण प्रदान किया। मराठी के सुप्रसिद्ध कवि मोरोपन्त भी अहिल्याबाई की कीर्ति सुनकर महेश्वर आए थे। मोरोपन्त मराठी के प्रसिद्ध कवि एवं भक्त थे। उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वह बिना किसी चाटुकारिता के अपनी बात सीधे-सीधे कहते थे। गंगा स्नान करते समय एक बार उनके हृदय से सहज ही अहिल्याबाई के संदर्भ में पद निकल पड़ा-

"देवी ! अहिल्याबाई यावी भेटावयास सत्वर ती।
तू पुण्य कीर्ति है ही गंगे दोधीजणी ही सत्वर ती।।

अर्थात हे गंगे, मैं अहिल्याबाई के दर्शन करूंगा। जैसे तुम संसार में प्रसिद्ध हो, उसी तरह वह भी प्रसिद्ध

है। तुम दोनों से संसार का उपकार होता है।

अपने भ्रमण के दौरान जब मोरोपंत उत्तर भारत की तरफ आए तो उन्होंने अनेक तीर्थ स्थानों के दर्शन किए। वहां उन्होंने अनुभव किया कि अहिल्याबाई द्वारा निर्मित विभिन्न मंदिर, धर्मशालाएं, कुएं और बावड़ियां आदि मौजूद हैं। साथ ही अनेकों स्थानों पर उन्हें अन्नसत्र एवं दानधर्म के कार्य विधिवत चलते दिखाई दिए। अहिल्याबाई द्वारा किए गए सामाजिक एवं धर्मार्थ कार्यों को देखकर मोरोपंत की अहिल्याबाई के प्रति श्रद्धा और भक्ति बढ़ती ही गई। कवि मोरोपंत ने निश्चय किया कि महेश्वर जाकर उनका दर्शन अवश्य करेंगे। जब कवि मोरोपंत महेश्वर पहुंचे तो वहां पर उन्हें अहिल्याबाई को सामने से देखने का अवसर प्राप्त हुआ। अहिल्याबाई को प्रत्यक्ष देखकर कवि भाव विभोर हो उठे। देवी ने भी कवि के आदर में कोई कमी नहीं की। उस दृश्य को कवि मोरोपंत ने मराठी भाषा में बहुत ही सुंदर शब्दों में चित्रित किया है -

श्रीहरि हरभक्ता तू देवि अहल्ये वरा धरा भूषा।
पूषा तुज साधु म्हणे ख्याता तुज सम न वाणतनुभूषा।।

अर्थात हे देवी अहिल्या, तुम हरि-हर की परम भक्त हो। अपनी भक्ति के कारण तुम पृथ्वी का श्रेष्ठ आभूषण बन गई हो। सूर्य भी तुम्हारी प्रशंसा करता है। बाण की पुत्री भी तुम्हारे समान प्रसिद्ध नहीं है।

अहिल्याबाई के दरबार में आई देश-विदेश से अनेक कवित्रियां भी आई। उस समय स्कॉटलैंड की कुमारी जोन बेली नाम की एक सुप्रसिद्ध कवित्री अहिल्याबाई के समय जीवित थी। इस महिला ने अहिल्याबाई की प्रशंसा में एक छोटी-सी पुस्तक लिखी है। इसी तरह सुप्रसिद्ध इतिहासकार तथा मध्य भारत के पोलिटिकल एजेंट सर मलकाम ने अहिल्याबाई के संबंध में अनेको प्रमाणित तथ्य प्रस्तुत किए हैं। भारत के तत्कालीन वायसराय लार्ड एलनबरो ने प्रथम अफगान युद्ध के बाद महाराजा हरिराव होल्कर को लिखे पत्र में अहिल्याबाई की महानता का बड़े गौरवपूर्ण शब्दों में उल्लेख किया था। इसी प्रकार पंडित कृष्ण शास्त्री चिपलणकर, सुप्रसिद्ध विद्वान इतिहासकार राम बहादुर चिंतामणि विनायक वेद एवं प्रसिद्ध इतिहासकार यदुनाथ सरकार आदि ने अहिल्याबाई के बारे में अपने ग्रंथों में विस्तार से लिखा है। इससे पता चलता है कि अहिल्याबाई तत्कालीन भारतीय इतिहास की न केवल एक सफल राजनीतिक दृष्टिकोण रखने वाली महान शासिका थी, बल्कि साहित्य और कला के प्रति उनके द्वारा किए गए संरक्षण-कार्यों का भी विशेष महत्व है।

भारतीय संस्कृति में सार्थक ज्ञान की प्राप्ति और विद्या का अध्ययन-अध्यापन प्राचीन काल से ही ब्राह्मणों का विशेष दायित्व भारत में माना जाता रहा है। बीच के कालखण्डों में देश के भीतर विभिन्न परिस्थितियों में बाह्य आक्रमणों के कारण ब्राह्मण एवं धर्म को बहुत हानि पहुंची थी। अहिल्याबाई ने उस कालखंड में हुई ज्ञान की क्षति को अपने अदम्य साहस से असाधारण बना दिया। देशभर में मंदिर बनने लगे और मंदिर और घर ब्राह्मणों के पूजा-पाठ एवं वेद मंत्रों के प्रेरक स्वरों से गूंजने लगे। अहिल्याबाई ने देश भर के विद्वानों, कीर्तनकारों, पंडितों, कर्मकांडियों, ज्योतिषियों आदि को महेश्वर में बुलाकर उनका सम्मान एवं संरक्षण और आश्रय का प्रबंध कराया। परिणाम यह हुआ कि वर्षों बाद भारतीय कला और साहित्य को ज्ञान के संदेशवाहकों को राज्य का आश्रय प्राप्त हुआ, जिससे ज्ञान और कला का प्रसार बढ़ने लगा। इस प्रकार एक साधारण परिवार में जन्मी अहिल्याबाई नाम मात्र की शिक्षा होते हुए भी एक श्रेष्ठ और आदर्श शासिका दिखाई पड़ती हैं। उन्होंने भले ही किसी ग्रन्थ की रचना नहीं की परन्तु उनका जीवन परम प्रेरणामयी एवं लोकोपयोगी खुले ग्रन्थ के समान है और इस ग्रन्थ के हर पृष्ठ में समाज के सुख और शांति का सन्देश है जो भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। ■

अहिल्याबाई तत्कालीन भारतीय इतिहास की न केवल एक सफल दृष्टिकोण रखने वाली महान शासिका थीं, बल्कि साहित्य और कला के प्रति उनके द्वारा किए गए संरक्षण-कार्यों का भी विशेष महत्व है। उनका पूरा जीवन लौकिक उन्नति और पारलौकिक कल्याण के लिए समर्पित रहा।

नारी शक्ति की प्रतिमूर्ति

■ अश्वनी शर्मा

महारानी अहिल्याबाई होल्कर (31 मई 1725-13 अगस्त 1795) भारत के मराठा मालवा साम्राज्य की रानी थीं। वह भारत की सबसे दूरदर्शी महिला शासकों में से एक थी तथा अपनी बुद्धिमत्ता, साहस और प्रशासनिक कौशल के लिए व्यापक रूप से जानी जाती हैं। अहिल्याबाई के पति खंडेराव होल्कर 1754 में कुंभेर के युद्ध में मारे गए तथा बारह साल बाद उनके ससुर मल्हार राव होल्कर की भी मृत्यु हो गई। उसके एक वर्ष पश्चात उन्हें मालवा साम्राज्य की रानी का कार्यभार पेशवा के द्वारा सौंप दिया गया। उसके पश्चात वर्षों तक अहिल्याबाई ने मालवा पर न्यायपूर्ण, बुद्धिमान और ज्ञानपूर्ण तरीके से शासन किया। रानी अहिल्याबाई होल्कर नारी शक्ति की एक जीवंत प्रतिमूर्ति हैं, जिन्होंने अपने चरित्र और आंतरिक क्षमता के बल पर राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने का कार्य किया। उन्होंने धर्म का पालन करने और कराने के साथ ही भारतीय संस्कृति के पुनरुद्धार के लिए अनेकों प्रयास किए। इसीलिए उन्हें "पुण्यश्लोक अहिल्याबाई" के नाम से भी जाना जाने लगा, जिसका अर्थ है एक दोषरहित चरित्र। तत्कालीन समय में अहिल्याबाई होल्कर का योगदान मात्र सामाजिक न होकर राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, योजनागत, कूटनीतिक तथा राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में भी रहा है।

अहिल्याबाई होल्कर ने अपनी राज्यशैली, धर्मप्रणायता, चतुरता तथा बुद्धिमता से समाज विकास तथा राष्ट्र विकास जैसे विभिन्न क्षेत्रों में न केवल योगदान दिया बल्कि भारत में एक आत्मनिर्भर, स्वतंत्र तथा मजबूत महिला शासक की छवि भी प्रस्तुत की, जो कि एक लंबे समय तक महिलाओं को प्रोत्साहित करती रही। 18वीं सदी में

मुग़लों तथा अन्य आक्रमणकारी शासकों के कारण भारतीय अनेकों समस्याओं का सामना कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर उनकी कामयाबी व्यापक स्तर पर भारतीयों के मनोबल को भी कमजोर कर रही थी। अहिल्याबाई होल्कर जैसी वीरांगनाओं के योगदान के कारण ही उस समय पर भारतीयों के मनोबल को मजबूत किया जा सकता था।

अहिल्याबाई निजी जीवन के साथ-साथ सार्वजनिक जीवन में भी आदर्शवाद में विश्वास रखते हुए समाज सुधार करना चाहती थी। उन्होंने राज्य नीति को पहले अपने घर से ही प्रारम्भ करते हुए अपने पति को सही मार्ग पर लाने हेतु धर्म का सहारा लिया, उन्हें धार्मिकता की ओर प्रेरित किया। साथ ही युद्ध कला में भी उनकी रूचि विकसित करने का कार्य किया।

अहिल्याबाई होल्कर की सफलता में उनके पिता

मानकोजी शिंदे जी का भी अहम् योगदान रहा। तत्कालीन समय में महिलाओं की शिक्षा की स्थिति उतनी व्यवस्थित नहीं थी। ऐसे में उनके पिता ने उन्हें पढ़ना-लिखना सिखाया। अंततः राज्य की बागड़ोर संभालने के पश्चात उन्होंने नर्मदा नदी के तट पर स्थित होल्कर राजवंश की राजधानी के रूप में महेश्वर (मध्य प्रदेश में) को स्थापित किया।

राष्ट्रव्यापी दृष्टिकोण

अहिल्याबाई का सबसे बड़ा योगदान यह था कि उन्होंने विदेशी आक्रांताओं के भारत एक पूर्ण राष्ट्र नहीं है के विचार को चुनौती दी तथा भारत की सभ्यता और सांस्कृतिक अस्मिता को पुनर्जीवित करने हेतु केदारनाथ, गंगोत्री, बद्रीनाथ, द्वारका, गया, वाराणसी, रामेश्वरम और पुरी जैसे विभिन्न स्थानों पर मंदिरों और तीर्थयात्रियों के विश्राम गृहों का जीर्णोद्धार और पुनर्निर्माण किया। इनके माध्यम से उन्होंने एक अखंड और पवित्र भारत की छवि प्रस्तुत की, जिसनें भविष्य में शासकों तथा धार्मिक गुरुओं के लिए न सिर्फ एक प्रोत्साहन का कार्य किया, बल्कि वृहद भारत और उसकी आत्मा की छवि को भी सभी के समक्ष रखा। अहिल्याबाई होल्कर उन प्रथम लोगों में से एक थी, जिन्होंने यह समझा कि भारत की आत्मा धर्म और आध्यात्मिकता में है।

जहां एक ओर अन्य भारतीय शासक अपने राज्य के पवित्र स्थलों के संरक्षण का कार्य कर रहे थे अहिल्याबाई ने उनका 'राष्ट्रीयकरण' किया। उनके राष्ट्रव्यापी दृष्टिकोण ने भौगोलिक और राजनीतिक रूप से विभाजित भारत में प्राचीन काल से राष्ट्र के रूप में भारत के धार्मिक तथा भावनात्मक आधार को बल दिया। अहिल्याबाई ने एक ऐसे भारत को एकत्रित करने का कार्य किया, जिसे कई शताब्दियों से राजनीतिक, आध्यात्मिक और भौगोलिक रूप से विभाजित किया गया था। धर्म के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए प्रयास मुख्य रूप से दो पहलुओं पर केंद्रित थे- पवित्र स्थलों और तीर्थस्थलों को पुनर्स्थापित और पुनर्जीवित करना तथा भारतीय वास्तुकला का पुनरुद्धार और संवर्धन करना।

अहिल्याबाई होल्कर का तीस वर्ष का शासन एक स्वर्णिम काल माना जाता है। उन्होंने अपने राज्य के गरीब तथा संघर्षरत लोगों के प्रति दया भाव रखते हुए बहुत कम मात्रा में कर पद्धति बनाई और किले, सड़कें, कुएं और यात्रियों हेतु विश्रामगृह इत्यादि बनवाए। पूरे राज्य में सड़कों के किनारे पेड़ लगवाए ताकि जनमानस को छांव प्राप्त हो सके।

अहिल्याबाई द्वारा किए गए राज्य संचालन के महत्व को इस आधार पर समझा जा सकता है कि जिस समय पर वह शासन सम्भाल रहीं थी, उस समय देश के विभिन्न हिस्सों में अराजकता का माहौल था। फिर भी आक्रांता और अन्य असामाजिक तत्व अहिल्याबाई के साम्राज्य पर आंख उठा कर भी नहीं देखते थे। धर्म प्रचार के लिए उन्होंने रामायण, महाभारत तथा पुराणों के

जहां एक ओर अन्य भारतीय शासक अपने राज्य के पवित्र स्थलों के संरक्षण का कार्य कर रहे थे, वहीं अहिल्याबाई ने उनका 'राष्ट्रीयकरण' किया। उनके राष्ट्रव्यापी दृष्टिकोण ने भौगोलिक और राजनीतिक रूप से राष्ट्र के रूप में भारत के धार्मिक तथा भावनात्मक आधार को बल दिया।

पाठ के कार्यक्रम प्रारंभ किए, जिनके माध्यम से आम जनमानस तक धार्मिक ग्रंथों को पहुंचाने का प्रयास किया गया।

लोक कल्याणकारी विकास

अहिल्याबाई होल्कर नें धार्मिक तथा सांस्कृतिक विकास हेतु धर्म का सन्देश जन-जन तक पहुंचाया। साथ ही उन्होंने राज्य के आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने हेतु औद्योगीकरण को भी प्रोत्साहन दिया। 11 दिसंबर 1767 को अहिल्याबाई होल्कर को पेशवा की ओर से मालदा की शासक के रूप में स्वीकार्यता मिली, उसके पश्चात् से ही अहिल्याबाई ने न्यायिक, बुद्धिमतापूर्ण तथा सुविज्ञ तरीके से शासन चलाया। उन्होंने राज्य में शांति समृद्धि तथा

स्थायित्व को स्थापित किया तथा राजधानी महेश्वर को शिक्षा, संगीत, कला, उद्योग क्षेत्र में अव्वल दर्जे पर ले आईं। अपने शासन के दौरान उन्होंने मालवा की राजधानी को नर्मदा नदी के किनारे बसे एक छोटे से शहर महेश्वर में स्थानांतरित कर दिया। वहां उन्होंने एक वृहद कपडा उद्योग की स्थापना की जो कि आज भी एक महत्वपूर्ण आर्थिक इकाई के रूप में कार्य कर रहा है।

अहिल्याबाई नें दैनिक संवाद के माध्यम से आम जनमानस के विषयों को जान कर समस्याओं का समाधान किया और लोककल्याणकारी नीतियों को लागू किया। अहिल्याबाई द्वारा किए गए कल्याणकारी कार्यों से लेकर बौद्धिक विकास तक के कार्यों के चलते ही उनको एक "दार्शनिक रानी" के रूप में देखा जाता है।

सर्वप्रथम अहिल्याबाई होल्कर ने सती प्रथा की अमानवीय और भेदभावपूर्ण प्रथा का पुरजोर विरोध किया तथा जनजागरण प्रारंभ किया। कुछ लोगो ने इस कार्य को चुनौती देने का प्रयास किया, परन्तु अहिल्याबाई मजबूती के साथ इसके विरुद्ध कार्य करती रही। उन्होंने राज्य की विधवा महिलाओं की स्थिति में भी सुधार लाते हुए दो प्रावधान किए। इसमें पति के देहांत उपरांत उनकी संपत्ति रखने का अधिकार दिया गया और पुत्रहीन महिलाओं को पुत्र गोद लेने का अधिकार भी मिला।

राष्ट्रव्यापी दृष्टिकोण

अहिल्याबाई होल्कर अपने ससुर मल्हार राव की राजकार्य में सहायता किया करती थी। सर मालकम के अनुसार "पुराने कागज़ात को देख कर ऐसा लगता है कि जब भी मल्हार राव किसी काम से अपने शहर से बाहर जाते थे, तो राज-काज सम्बंधित सभी कार्य अहिल्याबाई को सौंप कर जाते थे। यही वह समय भी था, जब अहिल्याबाई ने राज्य कला में निपुणता हासिल की तथा समय आने पर उस ज्ञान का सही लाभ भी उठाया"।

अहिल्याबाई होल्कर तथा अन्य शासकों, जिनमें मल्हारराव भी शामिल हैं, में महत्वपूर्ण अंतर दृष्टिकोण का था। अहिल्याबाई होल्कर मात्र अपने साम्राज्य की ही नहीं, वरन पूरे राष्ट्र में प्रबुद्ध शासन की किरण, प्रशासनिक कौशल, और सांस्कृतिक पुनर्जागरण की द्योतक के रूप में विख्यात हुई। उन्होंने स्वयं को अपने प्रान्त तथा साम्राज्य तक सीमित न करते हुए समूचे राष्ट्र के सर्वांगीण विकास को केंद्र में रख कर एकता का मूल मंत्र दिया तथा राष्ट्र के विभिन्न हिस्सों में हिन्दू अस्मिता का प्रचार प्रसार किया। मात्र अपने साम्राज्य तक ही सीमित न रह कर उन्होंने पूरे भारत के स्तर पर यह सन्देश देने का प्रयास किया कि सम्पूर्ण भारत एक राष्ट्र है। इसके लिए उन्होंने उत्तर दिशा में हिमालय में गंगोत्री और केदारनाथ, पूर्व दिशा में पुरी (ओडिशा) और दक्षिण दिशा में रामेश्वरम (तमिलनाडु) तक मंदिरों का निर्माण कराया। इससे भारतीयों के मन में अपने

सर्वप्रथम अहिल्याबाई होल्कर ने सती प्रथा की अमानवीय और भेदभावपूर्ण प्रथा का पुरजोर विरोध किया तथा जनजागरण प्रारंभ किया। कुछ लोगों ने इस कार्य को चुनौती देने का प्रयास किया, परन्तु अहिल्याबाई मजबूती के साथ इसके विरुद्ध कार्य करती रही।

धर्म और संस्कृति के प्रति सकारात्मक भाव संचार हुआ और मंदिरों के निर्माण तथा धर्म-कर्म के कामों को जन-जन तक पहुंचा कर उन्हें एकता के सूत्र में पिरोने का कार्य किया।

शासक नहीं, संत की भूमिका

अहिल्या बाई होल्कर एक ऐसी शासक थी, जिन्हें मात्र एक शासक के रूप में ही नहीं वरन एक संत के रूप में भी याद किया जाता है। भारत के प्रथम प्रधानमत्री जवाहर लाल नेहरू अपने लेख डेस्टिनी ऑफ़ इंडिया (1946) में लिखा है कि अहिल्याबाई के तीस वर्षों का शासन उत्कृष्ट व्यवस्था तथा सुशासन का उदाहरण प्रस्तुत करता है। इसके कारण सामान्य जन मानस का विकास

संभव हुआ। अहिल्याबाई एक ऐसी सक्षम शासक और संगठनकर्ता थी, जिन्हे एक संत के रूप में भी देखा जाता था"।

एनी बेसेंट (थियोसॉफिकल सोसायटी की संस्थापक) ने अहिल्याबाई होल्कर के शासन के विषय में कहा है कि उनके शासन में सड़कों को दोनों तरफ से वृक्षों से सुसज्जित कर रखा था। राहगीरों तथा अन्य नागरिकों के लिए विभिन्न संसाधन जैसे कुएं और विश्रामघर बनाए गए थे। गरीब तथा बेघर लोगों की बुनियादी आवश्यकताओं का विशेष ध्यान रखा गया था। समाज के लगभग सभी वर्गों में अहिल्याबाई सम्मानीय थीं,। इसीलिए

अहिल्याबाई होल्कर को सम्मान से लोग राजमाता, महारानी, पुण्यश्लोक तथा वीरांगना इत्यादि उपाधियों से सुशोभित करते हैं। उनके सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक, प्रशासनिक तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सम्बन्धी योगदानों को पूरे भारत में एक आदर्श व्यवस्था के रूप में देखा जाता है।

उन्हें एक संत के रूप में याद किया जाता है।

सामाजिक समरसता की सूत्रधार

अहिल्याबाई होल्कर ने अपने राज्य की कमज़ोरी का अनुमान लगाकर आक्रमणकारियों द्वारा घेर लिए जाने के बावजूद अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए उल्लेखनीय साहस दिखाया। अपने सैनिकों का कुशल नेतृत्व करते हुए उन्होंने दुश्मन के आक्रमण को अप्रभावी कर दिया। राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु एक ओर अहिल्याबाई ने चोर-लुटेरों की गतिविधियों को नियंत्रित किया, वहीं दूसरी ओर राज्य के शत्रुओं उदयपुर के राजा जगत सिंह, रामपुरा के सरदार चंद्रावत माधव सिंह, गंगाधर चंद्रचूड़, दादा राघोबा इत्यादि से भी राज्य को सुरक्षित रखा। युद्ध स्थिति में अपने साहस तथा कुशलता के चलते विरोधियों को लोहे के चने चबाने पर मजबूर कर दिया।

मल्हारराव होल्कर की मृत्यु के पश्चात ही अहिल्याबाई होल्कर ने अपने समस्त धन पर तुलसी दल रख कर उसको कृष्णार्पण कर दिया और उसे ईश्वरीय कार्यों में लगाने का निर्णय लिया। उन्होंने यह सिद्ध किया कि शासक का धर्म मात्र सेना को लड़ने भेजना ही नहीं वरन आवश्यकता पड़ने पर स्वयं भी उसका भाग बन कर राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना होता है।

अहिल्याबाई होल्कर को सम्मान से लोग राजमाता, महारानी, पुण्यश्लोक तथा वीरांगना इत्यादि उपाधियों से सुशोभित करते हैं। उनके सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक, प्रशासनिक तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सम्बन्धी योगदानों को पूरे भारत में एक आदर्श व्यवस्था के रूप में देखा जाता है। अहिल्याबाई के शासन का महत्व महेश्वर राजधानी, उसके घाटों की सुंदरता, किलों की मजबूती, मंदिरों और गलियों की खूबसूरती को देखने से समझ आता है। एक शासक होने के बावजूद भी अहिल्याबाई अत्यंत सामान्य और सादगी भरा जीवन व्यतीत करती थी। अहिल्याबाई एक आदर्श महिला शासक थी जिन्होनें न मात्र अपने राज्य को संभाला, बल्कि राज्य की रक्षा की, देश की एकता और अखंडता की रक्षा की, और सामाजिक समरसता सुनिश्चित की।

अहिल्याबाई को भारतीय समाज में साहस, बलिदान, त्याग और आदर्श की मूर्ति के रूप में याद किया जाता है। अंततः ऐसा कहा जा सकता है कि अहिल्याबाई होल्कर के विचार तथा कार्यों को वर्तमान में भी व्यापक स्तर पर लागू करने की आवश्यकता है। वर्तमान समय में विश्व पर्यावरणीय ह्रास से ग्रसित है, लेकिन अहिल्याबाई होल्कर पहले ही पर्यावरण के महत्व को जान चुकी थी। सुरक्षा के क्षेत्र में अहिल्याबाई से कूटनीति तथा राष्ट्रीय रक्षा हेतु कठोर निर्णय लेना सीखा जा सकता है। साथ ही आर्थिक क्षेत्र में जनता से जुडी हुई नीतियों को बनाना, उनके प्रश्नों को सुनना और उनकी सहायता करने का प्रयास करना भी सीखा जा सकता है। ■

विद्यार्थियों की आर्थिक बाधाओं को दूर करेगी पीएम विद्यालक्ष्मी योजना

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम विद्यालक्ष्मी नामक एक नई योजना को अपनी स्वीकृति दे दी है। इस योजना का उद्देश्य मेधावी विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि वित्तीय बाधाएं किसी भी विद्यार्थी को उच्च शिक्षा प्राप्त करने से न रोकें। पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के तहत, गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा संस्थान (क्यूएचईआई) में प्रवेश लेने वाला कोई भी विद्यार्थी ट्यूशन फीस की पूरी राशि और पाठ्यक्रम से संबंधित अन्य खर्चों के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों से गिरवी एवं गारंटर मुक्त ऋण प्राप्त करने का पात्र होगा। यह योजना एक सरल, पारदर्शी एवं विद्यार्थियों के अनुकूल प्रणाली के माध्यम से संचालित की जाएगी, जो अंतर- संचालनीय और पूरी तरह से डिजिटल होगी।

जानकारी के अनुसार योजना को एनआईआरएफ रैंकिंग द्वारा निर्धारित देश के शीर्ष गुणवत्ता वाले उच्च शिक्षण संस्थानों में लागू किया जाएगा। योजना में एनआईआरएफ के समग्र, श्रेणी-विशिष्ट और डोमेन-विशिष्ट रैंकिंग में शीर्ष सौ में स्थान रखने वाले सभी एचईआई (सरकारी एवं निजी) शामिल हैं। एनआईआरएफ रैंकिंग में 101-200 में स्थान रखने वाले राज्य सरकार के उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) और केन्द्र सरकार द्वारा प्रशासित सभी संस्थानों को इसमें शामिल किया गया है। इस सूची को एनआईआरएफ के नवीनतम रैंकिंग का उपयोग करके हर वर्ष अद्यतन किया जाएगा और आरंभ 860 योग्य क्यूएचईआई से होगी, जिसमें 22 लाख से अधिक विद्यार्थी शामिल होंगे जो अपनी इच्छानुसार संभावित रूप से पीएम-विद्यालक्ष्मी का लाभ उठा सकेंगे। योजना में 7.5 लाख रुपए तक की ऋण राशि के लिए, विद्यार्थी बकाया डिफॉल्ट के 75 प्रतिशत की क्रेडिट गारंटी के भी पात्र होंगे। इससे बैंकों को इस योजना के तहत विद्यार्थियों को शिक्षा ऋण उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी। इसके साथ ही जिन विद्यार्थियों की वार्षिक पारिवारिक आय आठ लाख रुपए तक है और वह किसी अन्य सरकारी छात्रवृत्ति या ब्याज छूट योजनाओं के तहत लाभ के पात्र नहीं हैं, उन्हें दस लाख रुपए तक के ऋण पर अधिस्थगन अवधि के दौरान तीन प्रतिशत की ब्याज छूट भी प्रदान की जाएगी। योजना में उन विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी जो सरकारी संस्थानों में अध्ययनरत हैं और जिन्होंने तकनीकी या व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का विकल्प चुना है। योजना के लिए 2024-25 से 2030-31 के मध्य 3,600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। योजना के लिए एकीकृत पोर्टल "पीएम-विद्यालक्ष्मी" उपलब्ध होगा, जिस पर विद्यार्थी सभी बैंकों द्वारा उपयोग की जाने वाली सरलीकृत आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से शिक्षा ऋण के साथ-साथ ब्याज छूट के लिए आवेदन कर सकेंगे। ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

सुधी पाठकों!

शिक्षा क्षेत्र की प्रतिनिधि पत्रिका के रूप में 'राष्ट्रीय छात्रशक्ति' नवम्बर 2024 अंक आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। यह अंक महत्वूर्ण लेख एवं विभिन्न समसामयिक घटनाक्रमों व खबरों को समाहित किए हुए हैं। आशा है, यह अंक आपके आवश्यकताओं के अनुरूप उपादेय साबित होगा। कृपया 'राष्ट्रीय छात्रशक्ति' से संबंधित अपने सुझाव व विचार हमें नीचे दिए गए संपादकीय कार्यालय के पते अथवा ई-मेल पर अवश्य भेजें : -

'राष्ट्रीय छात्रशक्ति'
26, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग,
नई दिल्ली-110002
फोन : 011-23216298
www.chhatrashakti.in
rashtriyachhatrashakti.abvp@gmail.com
www.facebook.com/Rchhatrashakti
www.twitter.com/Rchhatrashakti
www.instagram.com/ Rchhatrashakti

75 Years of Constitution of Bharat

■ Dr. Pankaj Jamtani

Seventy-five years after the inception of Constitution of India, there is an echoing call from all corners, to interpret Bharat's Constitution in a way that reflects indigenous values, sensibilities, and cultural heritage. An interpretation that is "Bhartiya" in essence would deepen our constitutional spirit. Such an approach would respect India's unique values and historic wisdom, fostering an interpretation that upholds Bharatiya philosophy and ideals. Though, the Indian Constitution, adopted in 1949 and enacted 26 Jan, 1950, has evolved as a framework that upholds Bharat's ancient ethos while embracing modern democratic values. As we celebrate 75 years of the Constitution, we reflect on its remarkable journey as a cornerstone for India's development, a guiding light for us as a citizen, and a document with the flexibility to adapt and address the changing needs of society. Bharat's Constitution reflects resilience, ensuring equality and justice across generations. This article highlights the positive impact of 75 years of the Indian Constitution. Through its visionary framework, the Constitution has empowered citizens, uplifted marginalized communities, and laid a strong foundation for a vibrant, inclusive nation.

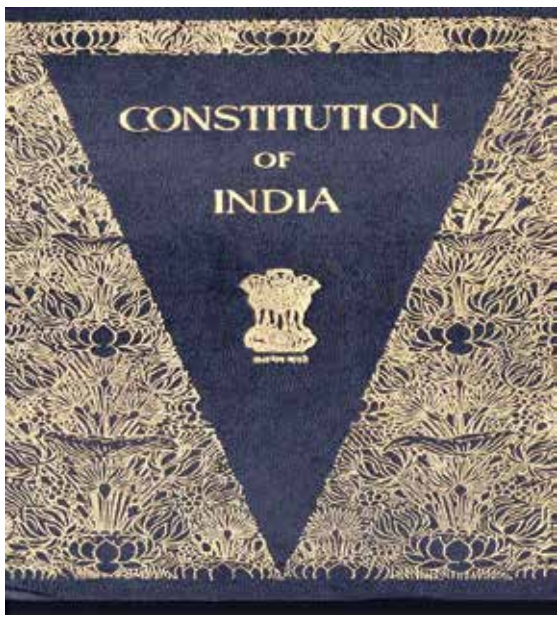

Building an Inclusive Nation

One of the most profound commitments of the Constitution is its affirmative action policies, embodied in the reservation system for Scheduled Castes (SC), Scheduled Tribes (ST) and Other Backward Classes (OBC). Recognizing the historical injustices faced by these communities, the framers of the Constitution ensured that provisions for reservations were enshrined to promote social and educational empowerment. This vision is encapsulated in Articles 15, 16, and 46, which emphasize the state's responsibility to promote the educational and economic interests of these groups and protect them from social injustice and exploitation. Over time, these provisions have provided SCs, STs and OBCs with access to opportunities in education, government jobs, and political representation, enabling many from marginalized backgrounds to break the barriers of systemic discrimination and achieve upward mobility. In recent decades, affirmative action policies have expanded to address new social and economic

challenges faced by these communities. The 73rd and 74th Constitutional Amendments, for instance, reserved seats in Panchayati Raj Institutions for SCs, ST and women, which has fostered grassroots empowerment and political inclusion. This decentralized representation has enabled marginalized voices to participate directly in decision-making processes that impact their daily lives, reinforcing the democratic values upon which the Constitution was built.

Empowering Constitutional Institutions

The Constitution set up essential institutions to uphold democracy and Law which have become pillars of Bharat's growth story. The Election Commission of India (ECI), Comptroller and Auditor General (CAG), Union Public Service Commission (UPSC) and various other bodies have functioned with remarkable autonomy, acting as protectors of democratic processes, financial accountability, and administrative efficiency. These institutions not only promote transparency and integrity but also symbolize the commitment to uphold democratic values, giving Bharat a reputation for robust institutional integrity. Strengthening these institutions, therefore, is not only a matter of governance but a testament to Bharat's dedication to upholding the Constitution's vision of justice, liberty, equality, and fraternity for all. With Bharat's journey of 75 years, deeply rooted in constitutional principles, the continued strength and integrity of these institutions will remain essential in charting a path forward that is both democratic and distinctly Indian.

Judiciary : Safeguarding Justice and Rights

A remarkable feature of the Indian Constitution is the independence granted to the judiciary. The framers envisioned a judiciary free from executive influence, ensuring that citizens could trust the judiciary to protect their rights and uphold justice. Over 75 years, the judiciary has delivered landmark judgments that expanded the scope of fundamental rights, reinforced the values of equality and non-discrimination, and upheld constitutional morality. Judicial independence has also strengthened the public faith. Recent Supreme Court judgments and legislative changes signal a renaissance in Bharat's socio-legal landscape, heralding a renewed era of unity, equality, and constitutional integrity. The abrogation of Article 370 has integrated Jammu and Kashmir more closely with the nation, while the Triple Talaq verdict and observations on the Uniform Civil Code reflect a commitment to gender justice and uniform rights. The Ram Janmabhoomi decision, with its emphasis on respectful resolution of historic disputes, has furthered social harmony. Together, these developments echo a revival of Bharat's core values, advancing an inclusive, empowered future.

The Constitution's Role in Socio-Economic Transformation

The Indian Constitution has been pivotal in promoting socio-economic transformation through a range of social reforms. Over the years, significant amendments and progressive judgments have expanded economic rights, labor rights, and protections for vulnerable groups. Through policy frameworks derived from constitutional mandates, Bharat has implemented transformative schemes like the Right to Education Act, MNREGA, and the National Food Security Act, which provide critical support to millions, ensuring access to education, employment, and essential resources for marginalized sections of society.

Conclusion

The framers of the Constitution of India were a remarkable group of visionary leaders, jurists, and scholars with a deep understanding of law, history, and social issues. Drawing inspiration from global principles and adapting them to Bharat's unique cultural fabric, they crafted a Constitution that balances democratic ideals with indigenous values. Their foresight and dedication to justice and unity laid the groundwork for our nation. As Bharat reflects on 75 years of its Constitution, we see not only a document of governance but a dynamic framework that has enabled transformative change across generations. This living document has adapted to meet the aspirations of an evolving society, becoming an anchor of social, economic, and political progress. Through its guiding principles, the Constitution has served as a roadmap for addressing injustices, empowering the underprivileged and shaping an inclusive nation. With each passing year, the Constitution remains a source of empowerment for every Indian, embodying the spirit of equality. The vision for the future is a Constitution that continues to protect and empower within the framework of Indian culture and thought, to truly embody the principles of a "Bhartiya Samvidhan." ■

I उत्तर प्रदेश I

बीएचयू कुलपति से मिला अभाविप प्रतिनिधिमंडल

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय (बीएचयू) की शोध प्रवेश प्रक्रिया में व्याप्त समस्या एवं विभिन्न अन्य अनियमितताओं के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) काशी विश्वविद्यालय इकाई लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। अभाविप का अनिश्चितकालीन प्रदर्शन गत 18 अक्टूबर को आरंभ हुआ था। इस दौरान विभिन्न स्तरों पर विश्वविद्यालय प्रशासन से संवाद के पश्चात भी कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकला। बाद में गत 22 अक्टूबर को परिसर भर में काली पट्टी बांध कर प्रदर्शन और फिर गत 25 अक्टूबर को आक्रोश मार्च का आह्वान किया गया।

इस दौरान अभाविप के नेतृत्व में छात्रों के मध्य सम्पर्क अभियान चलाया गया। परिणाम स्वरुप आक्रोश मार्च में बड़ी संख्या में छात्र सम्मिलित हुए। छात्रों ने शोध प्रवेश नियमावली वापस लेने के साथ ही अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए अपनी आवाज बुलंद की। इस दौरान अभाविप नेताओं ने कुलपति से मिलने एवं छात्रों से जुडी समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास किया, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने कोई ठोस कदम उठाने की आवश्यकता महसूस नहीं की।

बीएचयू आईआईटी के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेने के लिए गत 28 अक्टूबर को जब केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान आए तो अभाविप प्रतिनिधिमंडल ने मुलाक़ात करके शोध प्रवेश नियमावली, वित्तीय अनियमितता सहित अन्य मांगों को सामने रखा। मुद्दों की गंभीरता को देखते केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रधान ने कुलपति को अभाविप से बातचीत के निर्देश दिए। इसके बाद कुलपति ने अभाविप प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करके सभी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया। इसके बाद आंदोलन आगामी निर्णय तक स्थगित कर दिया गया।

अभाविप लंबे समय से जो मांगें कर रही हैं, उनमें गत चार वर्षों से बंद विश्वविद्यालय के वार्षिक युवा महोत्सव स्पंदन को पुनः प्रारम्भ करने, शोध प्रवेश प्रक्रिया नियमावली की त्रुटि दूर करने, लंका स्थित सिंह द्वार का जीर्णोद्धार प्रारम्भ करने सहित कई अन्य मांगे शामिल हैं। ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

...नहीं रही स्वर कोकिला शारदा सिन्हा

लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा को अपनी सुरीली आवाज़ से जन-जन को अवगत कराने वाली बिहार कोकिला तथा पद्म भूषण से सम्मानित शारदा सिन्हा का 72 वर्ष की आयु में गत 5 नवंबर की रात निधन हो गया। उनके निधन पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि बिहार एवं संपूर्ण देश के लिए अपूरणीय क्षति है।

अभाविप ने अपने शोक सन्देश में कहा कि उनके गीत सदैव देशवासियों की धड़कनों में गूंजते रहेंगे। दुख की घड़ी में अभाविप उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करती है। साथ ही छठी मईया से दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करने की प्रार्थना करती है। बिहार कोकिला शारदा सिन्हा का निधन अत्यंत पीड़ादायक है। स्थानीय भाषा में लोकगीत और लोक संस्कृति के सरंक्षण और संवर्धन के लिए उनका योगदान सदैव अविस्मरणीय रहेगा।

जानकारी हो कि स्वर्गीय शारदा सिन्हा ने मैथिली तथा भोजपुरी लोकगीतों को राष्ट्रीय मंच पर स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अभाविप उत्तर बिहार के प्रांत अध्यक्ष डा. अंजनी श्रीवास्तव ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनका निधन बिहार वासियों के लिए अपूरणीय क्षति है। यद्यपि आज वह हमारे बीच नहीं हैं, किंतु उनकी गायिकी लोगों के दिलों में सदैव रहेगी। बिहार का जनमानस उन्हें कभी नहीं भूल सकता है।

बिहार कोकिला के नाम से विख्यात शारदा सिन्हा लोक गीतों के लिए पहचानी जाती हैं। उन्होंने कई हिंदी फिल्मों के लिए भी गायन किया है। उन्हें उत्तर भारत की सांस्कृतिक राजदूत के रूप में भी देखा जाता है। बिहार और पूर्वांचल में छठ पर्व के दौरान शारदा सिन्हा की आवाज़ लगभग सभी घरों में गूंजती है। 1970 के दशक से लोक गीत के लिए स्वर देने वाली स्वर्गीय शारदा सिन्हा ने भोजपुरी, मैथिली और हिन्दी में कई लोकगीत गाए हैं। उनकी गायकी में बिहार से पलायन और महिलाओं के संघर्ष को काफ़ी जगह मिली है। फ़िल्म 'हम आपके हैं कौन' में उनके गीत को आज भी बेटियों की शादी के बाद विदाई के समय बजाया जाता है। 2018 में उन्हें नागरिक सम्मान पद्मभूषण से सम्मानित किया गया था। ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

डा. बिबेक देबरॉय का निधन

प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डा. बिबेक देबरॉय के निधन पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) ने शोक व्यक्त करते हुए उनकी आत्मा की शान्ति के लिए प्रार्थना की है। विख्यात अर्थशास्त्री डा. देबरॉय प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष थे। गत 1 नवंबर को 69 वर्ष की आयु में राजधानी दिल्ली में उनका निधन हो गया।

जानकारी हो कि 2015 में भुवनेश्वर में आयोजित अभाविप के 61वें राष्ट्रीय अधिवेशन में मुख्य अतिथि के रूप में डा. देबरॉय ने हिस्सा लिया था। अपने जीवन काल में डा. देबरॉय ने कई महत्वपूर्ण भूमिकाओं का निर्वहन किया। 2015 में उन्हें पद्मश्री और 2016 में उन्हें यूएस-इंडिया बिजनेस समिट में लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। एक उत्साही लेखक के रूप में उन्होंने कई पुस्तकें, शोध पत्र और लेख लिखे, जिसके माध्यम से उन्होंने आर्थिक सुधारों, रेलवे नीति और सामाजिक असमानताओं पर अंतर्दृष्टि साझा की। अर्थशास्त्र, नीति विषयों, संस्कृति, इतिहास, राजनीति आदि क्षेत्रों के संदर्भ में उनका चिंतन महत्वपूर्ण है। ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

भारत के स्वर्णिम इतिहास का साक्षी वैशाली गणतंत्र

साभार

■ याज्ञवल्क्य शुक्ल

पश्चिमी देश न्याय एवं स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में बार-बार अधिकारों की मौलिक गारंटी देने वाले दस्तावेज मैग्नाकार्टा और यूनान का हवाला देते हैं। इसी के माध्यम से वह भारत के प्रजातंत्र के इतिहास को नकारने का प्रयास भी करते हैं। भारत में महान भारतीय गणितज्ञ महर्षि बौधायन का सिद्ध गणितीय सूत्र पाइथागोरस का प्रमेय बन गया और भारत के बच्चे भी उसी का पाठ करने लगे। भारतीय इतिहास के साथ भी इसी तरह का दुस्साहस करने का प्रयास किया गया। लेकिन जब भारत के राष्ट्रवादी एवं विदेश के निष्पक्ष इतिहासकारों ने सच्चाई के साथ शोध किया तो भारत के स्वर्णिम इतिहास का उदय हुआ। जिस भारत को पश्चिम देश सपेरों का देश कहता था, उस देश में आज से 2800 वर्ष पहले ही प्रजातंत्र की नींव पड़ चुकी थी और उसकी व्यवस्था ठीक वैसी ही थी, जैसे आज के लोकतांत्रिक देशों में होती है।

काशी प्रसाद जयसवाल, अनंत सदाशिव अल्तेकर और योगेंद्र मिश्र जैसे विद्वानों ने अपने शोध कार्यों से वैशाली को विश्व के प्राचीनतम गणतंत्र के रूप में

स्थापित किया। प्रसिद्ध इतिहासकार जायसवाल ने अपनी रचना 'हिंदू पॉलिटी' में पूर्वाग्रही औपनिवेशिक श्रेष्ठता को चुनौती देते हुए लिखा है कि वैशाली में गणतांत्रिक राज्य था और प्राचीन काल से भारतीय जनतंत्र का व्यवहार करते रहे हैं। उन्होंने लिखा कि वज्जि संघ आधुनिक स्विट्जरलैंड और अमेरिका में पाई जाने वाली किन्हीं भी संस्थाओं से अधिक विकसित था। अपने अध्ययन के अंत में जायसवाल ने निष्कर्ष निकाला है कि हिंदुओं द्वारा की गई प्रगति की प्राचीन विश्व के किसी राजनीतिक संस्था ने बराबरी नहीं की है।

विश्व को गणतंत्र का पाठ पढ़ने वाले वैशाली गणराज्य का उदय लगभग 725 ईसा पूर्व (आज से लगभग 2800 वर्ष पहले) में यूनान के प्रादुर्भाव से पहले ही हो चुका था। इसका अस्तित्व लगभग 400 ईसा पूर्व तक रहा। वैशाली का नामकरण महाभारत काल के इक्ष्वाकु वंश के एक राजा विशाल के नाम पर हुआ है। राजा विशाल द्वारा बनवाया हुआ एक किला खंडहर के रूप में आज भी वैशाली में मौजूद है। वैशाली में गणतंत्र के उदय में मुख्य भूमिका लिच्छवि वंश ने निभाई। उन्होंने आठ कुलों को एकजुट करके अष्टकूल का निर्माण किया, जिन्हें वज्जि संघ कहा गया। इनका नेतृत्व लिच्छवि करते थे। वज्जि संघ में लिच्छवियों के अलावा ज्ञातृक और विदेह भी सबसे महत्वपूर्ण थे। इस संघ के राज्य का नाम वैशाली और उसकी राजधानी भी वैशाली ही थी। वज्जियों के गणतंत्र में उत्तर बिहार का एक बड़ा हिस्सा और नेपाल का तराई भाग शामिल था। पुराण, महाकाव्य, उपनिषद बौद्ध, जैन और तिब्बती साहित्य में इसके प्रमाण मिलते हैं।

पाणिनि की अष्टाध्यायी, कौटिल्य के अर्थशास्त्र और पतंजलि के महाभाष्य में वैशाली और इसके इतिहास के बारे में जो जानकारी मिलती है, उससे पता चलता है कि राजतंत्र की समाप्ति के बाद वैशाली में जो शासन स्थापित हुआ, उसको गण कहा गया। इस शासन तंत्र में कोई राजा नहीं था। इस राज्य में प्रत्येक परिवार का प्रधान राजा था। वज्जि गणतंत्र में बाहर के लोगों को नागरिकता प्रदान करने की भी व्यवस्था थी। बुद्ध ने महापरिनिर्वाण सूत्र (महापरिनिब्बाण सुत्त) में वज्जि गणतंत्र की सात विशेषताओं का उल्लेख किया है। इनमें वज्जियों की पूर्ण जनसभा का बार-बार होना, बैठक के माध्यम से राष्ट्रीय कर्तव्यों का पालन करना, वज्जि सभा द्वारा निर्मित कानून कानून एवं संस्थाओं के अनुसार सामाजिक व्यवहार, वृद्धों का सम्मान एवं अनुसरण, महिलाओं का सम्मान, और आम जनता को न्याय संगत संरक्षण, सुरक्षा और सहायता देना शामिल है।

वास्तव में वज्जि संघ सामान्य स्थिति वाले स्वतंत्र जनों का संघ था और संघ में सम्मिलित होने के बाद भी प्रत्येक की स्वायत्तता को अक्षुण्ण रखा गया था। शासन के निगमित रूपों को प्रजातंत्र की प्रमुख शक्ति माना जाता था। इन गणराज्यों की शासन प्रणाली लोकतांत्रिक थी और शासन के कार्यों का संचालन सभा और परिषद मिलकर करती थीं। सभा में 7707 राजा थे। कुछ ग्रन्थों में राजाओं की संख्या 5000 भी बताई जाती है। यह सभी परिवार के मुखिया होते थे। इसके साथ ही नौ निर्वाचित सदस्यों की एक छोटी सी परिषद होती थी, जो प्रशासन का कार्य संभालती थी। सभा और परिषद मिलकर काम करती थीं। दो सदनों के माध्यम से शासन की प्रणाली वैशाली के गणतंत्र ने ही पूरे विश्व को सिखाई है। आज भी विश्व के अधिकांश देश इसी प्रणाली का अनुसरण कर रहे हैं। महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए मतपत्र प्रणाली का भी उपयोग आज भी विद्यमान है। इसमें बहुमत के आधार पर मुद्दों का समाधान किया जाता था। कोई राजा नहीं था और गण के अध्यक्ष को ही राजा कहा जाता था। गणराज्यों के सभा भवनों में नियमित रूप से बैठकें होती थी। सभा भवनों को संथागार कहा जाता था। वर्तमान समय में संथागार को संसद या विधानसभा कहा जाता है।

वैशाली का टीला जिसे राजा विशाल का गढ़ कहा जाता है, सदियों पहले लिच्छवी संसद के रूप में कार्य करता था। इसमें सात हजार से अधिक लोगों के बैठने की क्षमता थी। 7707 राजाओं की आमसभा में से गणाध्यक्ष चुना जाता था। यह पद पैतृक नहीं था, बल्कि सभागार में आयोजित बैठक के दौरान मौजूद राजा उसका चयन करते थे। गणाध्यक्ष ही सभा की अध्यक्षता करता था। बैठक में शासन से

संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होती थी, जिसमें वित्त प्रशासन न्याय से संबंधित कानून पारित किए जाते थे। इन सभाओं में ज्यादातर कुलीन एवं जमींदार वर्ग के लोग होते थे। कुछ मामलों में सभी स्वतंत्र व्यक्तियों को भी शामिल किया जाता था। विवाद या सर्वसम्मति से निर्णय न होने की स्थिति में उस पर मत लिए जाते थे। मतदान को छंद कहा जाता था। मत प्रकट करने के लिए सदस्यों को शलाका (लकड़ी की छोटी तख्ती) दी जाती थी। यह विभिन्न मतों को प्रकट करने के लिए कई रंगों में रंगी होती थी। सर्वसम्मति से निर्णय नहीं होने पर बहुमत के आधार पर फैसला किया जाता था। गण परिषद की कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए सदस्यों की कम से

गणतंत्र की विशेषता लिच्छवी संविधान में निहित न्यायिक पद्धति में मिलती है। इसकी न्यायिक प्रक्रिया सात चरणों में संपन्न होती थी। कानूनी कार्यवाही बहुत लंबी होती थी और संदिग्ध अपराधी को एक के बाद एक अधिकारियों के न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत होना पड़ता था।

कम संख्या निर्धारित थी, जिसे गणपूर्ति कहते थे। संथागार के भीतर विनय का पालन करना पड़ता था यानी अनावश्यक बातचीत करना मना था। किसी प्रस्ताव के नियमतः पास होने पर उस पर फिर विचार नहीं होता था। परिषद की कार्यवाही का लिखित विवरण रखा जाता था।

इस गणराज्य में किसी व्यक्ति अथवा राजा का शासन नहीं बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं का शासन था। प्रशासन में राजा, कोषाध्यक्ष सेनापति जैसे अधिकारी शामिल थे। प्रसिद्ध इतिहासकार रमेशचन्द्र मजुमदार के अनुसार गणराज्यों में अनेक प्रशासनिक इकाइयां शामिल थीं, जिनमें से प्रत्येक इकाई अपने प्रशासनिक तंत्र के साथ एक लघु गणराज्य के रूप में कार्य करती थी। सरकार चलाने के लिए भूमि कर और श्रम साध्य कर लिया जाता था। अधिकांश स्थानीय प्रशासन ग्राम प्रधानों या प्रमुख परिवारों के द्वारा नियंत्रित एवं संचालित होते थे। वैशाली गणतंत्र के उत्थान में नगरों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भूमिपति क्षत्रिय नगरों में रहते थे और शिल्पियों के कार्यकलापों को प्रोत्साहन देते थे। वैशाली में बहुत ही सुदृढ़ और सुव्यवस्थित न्याय व्यवस्था का संचालन किया जाता था। गणतंत्र की विशेषता लिच्छवी संविधान में निहित न्यायिक पद्धति में मिलती है। इसकी न्यायिक प्रक्रिया सात चरणों में संपन्न होती थी। कानूनी कार्यवाही बहुत लंबी चौड़ी होती थी और संदिग्ध अपराधी को एक के बाद एक अधिकारियों के न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत होना पड़ता था।

सैकड़ों वर्ष पूर्व लिच्छवियों के नेतृत्व में वज्जि महासंघ ने प्रजातंत्र की जिस प्रणाली का आरंभ किया, उसी का अनुसरण कर विश्व के अनेक देशों में प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं का विकास हुआ। वर्तमान समय के अनुरूप चुने हुए प्रतिनिधियों का शासन संभालना, संसद की तरह संस्थागरों की बैठकों का आयोजन, सर्व समिति से निर्णय लेने की परंपरा, विरोध की स्थिति में मतदान करके निर्णय करना आदि वैशाली के गणतंत्र की देन है। कुछ आलोचक वैशाली के गणतंत्र की यह कहकर आलोचना करते हैं कि वहां सेवक वर्ग और महिलाओं को प्रवेश नहीं था। लेकिन वह यह नहीं बताते हैं कि वैशाली गणतंत्र के नीति निर्देशक सात तत्वों में एक तत्व केवल महिलाओं के लिए है, जिसमें उन पर किसी तरह का दबाव नहीं बनाने का निर्देश दिया गया है। इससे यह सिद्ध होता है कि उस समय महिलाओं की स्थिति काफी बेहतर थी। विश्व को सबसे पहले लोकतंत्र का पाठ वैशाली ने ही पढ़ाया, इसीलिए भारत भूमि ही लोकतंत्र की जननी है। वैशाली के संबंध में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है -

वैशाली जन का प्रतिपालक, विश्व का आदि विधाता।
जिसे ढूंढता विश्व आज, उस प्रजातंत्र की माता।
रुको एक क्षण पथिक,
इस मिट्टी पर शीश नवाओ। राज्य सिद्धियों की समाधि पर, फूल चढ़ाते जाओ। ■

'पर्यावरण अनुकूलन के लिए कार्य करें विद्यार्थी'

लखनऊ विश्विद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) लखनऊ महानगर के विकासार्थ विद्यार्थी आयाम की ओर से आयोजित दो दिवसीय मॉडल कॉन्फ्रेंस ऑफ यूथ-2024 का आयोजन किया गया। एपी सेन सभागार में आयोजित सम्मेलन का उद्घाटन आईआईआईटी (लखनऊ) के निदेशक डा. अरुण मोहन शेरी ने किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि प्लास्टिक मुक्त भारत का महाभियान पर्यावरणीय संतुलन बनाने में कारक सिद्ध होगा। इसके लिए सभी को मिलकर प्रयास करना होगा। भारत के शैक्षिक संस्थानों में पर्यावरणीय व्यवहार की शिक्षा और उसे समाज तक ले जाने में यह सम्मेलन काफी सहायक सिद्ध होगी। भारतीय युवाओं को पर्यावरण के प्रति चिंतन रखते हुए अपने दैनिक दिनचर्या में उनके अनुकूलन हेतु प्रयास भी करने की आवश्यकता है।

सम्मेलन में अभाविप के राष्ट्रीय मंत्री अंकित शुक्ला ने कहा कि पर्यावरण भारत की संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। भारत में सतयुग से लेकर द्वापर और त्रेता में भी मानव और पर्यावरण के मध्य मैत्री संबंध देखने को मिलते हैं। अवध प्रांत की उपाध्यक्ष प्रो. मंजुला उपाध्याय ने नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल पर कहा कि पृथ्वी पर सभी जीवन रूपों को अपने विकास के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसे कई स्रोतों से प्राप्त करते हैं। लेकिन यह विचार करना ही होगा कि प्लास्टिक का उपयोग किस तरह से कम किया जा सकता हैं। ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

आयुर्वेद जीवविज्ञान विषय नेट परीक्षा में सम्मिलित

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने आगामी दिसंबर सत्र में होने वाली राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) के लिए आयुर्वेद जीवविज्ञान को एक विषय के रूप में सम्मिलित करने का निर्णय लिया है। आयोग के अनुसार विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर दिसंबर 2024 से यूजीसी नेट के विषयों की मौजूदा सूची में आयुर्वेद जीवविज्ञान को एक अतिरिक्त विषय के रूप में जोड़ दिया गया है। दिसंबर-2024 से उम्मीदवार इस विषय का चयन कर सकते हैं, जो अंतःविषय ज्ञान और आयुर्वेद के प्राचीन विज्ञान को बढ़ावा देगा। इससे पहले इसी वर्ष जून में आयोग ने यूजीसी नेट दिसंबर-2024 परीक्षा के लिए विषयों की सूची में आपदा प्रबंधन विषय को शामिल करने की घोषणा की थी। उम्मीदवार यूजीसी नेट दिसंबर-2024 परीक्षा आवेदन पत्र भरते समय नए पेपर के लिए आवेदन कर सकेंगे। सम्मिलित किए गए नए विषय के लिए यूजीसी नेट पाठ्यक्रम आधिकारिक वेबसाइट ugcnetonline.in पर उपलब्ध है। ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

सिक्किम विश्वविद्यालय में अभाविप की ऐतिहासिक जीत

अभाविप पैनल के सभी प्रत्याशी जीते

सिक्किम विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। अभाविप ने छात्र संघ चुनाव में संयुक्त पैनल का गठन किया था और पैनल के सभी नौ प्रतिनिधियों को चुनाव में जीत मिली।

सिक्किम विश्वविद्यालय छात्र संघ के नव-निर्वाचित अध्यक्ष अनुप रेग्मी ने 379 वोटों से जीत हासिल की। जनकारी हो कि सिक्किम विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में प्रतिभाग करने वाले छात्र-छात्रा किसी भी संगठन से सीधे चुनाव नहीं लड़ सकते है। उन्हें अपनी विचारधारा का कोई पैनल बनाना होता है, जो चुनाव में हिस्सा लेता है। अबकी बार वामपंथी विचारधाराओं ने अपने पैनल को आइडिया नाम दिया था, जबकि अभाविप ने अपने विचार पैनल का नाम यूनाइटेड दिया था।

गत 9 नवम्बर को हुए चुनाव में यूनाइटेड पैनल ने नौ पदों पर प्रतिनिधि उतारे थे और सभी प्रतिनिधि विजयी घोषित हुए। सिक्किम की इतिहास में यह चुनाव ऐतिहासिक रहा, जिसमें पहली बार पूरे पैनल के प्रतिनिधि विजयी घोषित हुए। जीते हुए प्रतिनिधियों को गत 11 नवंबर को शपथ दिलाई गई। ■

अध्यक्ष-अनूप रेग्मी
उपाध्यक्ष - हिमांग्शु राज बोरा
महासचिव - थेंडुप नामग्याल भूटिया
संयुक्त सचिव - आकांक्षा प्रधान
कोषाध्यक्ष - उज्ज्वल भट्टाचार्जी
सचिव (शैक्षणिक मामले) - रिंचेनला शेरपा
सचिव (सामाजिक सेवा) - सरस्वती गुरुंग
सचिव (खेल) - सांगे छिरिंग लेप्चा
सचिव (सांस्कृतिक मामले)- अनुप्रीता रॉय चौधरी

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

दीपोत्सव कार्यक्रम में पांथिक उन्मादियों ने फैलाई हिंसा

राजधानी दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में आयोजित दीपोत्सव कार्यक्रम में पांथिक उन्मादियों तथा असामाजिक तत्वों द्वारा फैलाई गई हिंसा की अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) ने कड़ी निंदा की है। अभाविप ने जामिया प्रशासन एवं दिल्ली पुलिस से हिंसा करने वाले कट्टरपंथी तथा पांथिक उन्मादियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है।

जानकारी हो कि गत 22 अक्टूबर को जामिला मिल्लिया इस्लामिया में दीपोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। अभाविप के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में छात्र उत्साहित होकर दीप प्रज्ज्वलित करने के साथ ही रंगोली बना रहे थे। इसके विरोध में पांथिक उन्मादियों ने उपद्रव किया। रंगोली और दीयों को नष्ट करने के साथ ही उन्मादियों ने फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगाए। घटना के बाद पैदा हुए तनाव के बीच पहुंची पुलिस जांच में जुट गई। घटना विश्वविद्यालय के गेट नंबर-सात पर हुई।

अभाविप ने घटना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया आयोजित दीपोत्सव कार्यक्रम के दौरान बाहरी पांथिक उन्मादियों तथा असामाजिक तत्वों ने फ़िलिस्तीन ज़िंदाबाद के साथ ही अन्य उन्मादी नारे लगाए। दीपोत्सव के दीपों को तोडा गया, रंगोली को नष्ट कर दिया गया। विश्वविद्यालय प्रशासन चुपचाप देखता रहा। प्रश्न यह है कि क्या भारत के केंद्रीय विश्वविद्यालय में दीपावली मनाना या भारत माता की जय के नारे लगाना अपराध है? विश्वविद्यालय परिसर सभी विद्यार्थियों के लिए हैं। ऐसे में विश्वविद्यालय प्रशासन को दोषियों के साथ सख्ती से निपटने के लिए आगे आना चाहिए। ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

वामपंथियों ने किया भगवान श्रीराम का अपमान

राजधानी दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में एक बार फिर से वामपंथी छात्रों ने अपना असली चेहरा उजागर करते हुए भगवान श्रीराम का अपमान किया है। घटना उस समय हुई जब जेएनयू के साबरमती लॉन में आयोजित विश्वविद्यालय सामान्य बॉडी बैठक (यूजीबीएम) का आयोजन किया गया था।

यूजीबीएम की बैठक आंतरिक समिति (आईसी) के चुनावों और महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मामलों पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई थी। लेकिन बैठक के दौरान वामपंथी समर्थित जेएनयूएसयू ने महिला प्रतिनिधि को मंच देने से इंकार कर दिया। साथ ही चुने हुए काउंसलर्स को भी बोलने नहीं दिया। इसी दौरान एक वामपंथी कार्यकर्ता ने मंच से भगवान श्रीराम के विरुद्ध अमर्यादित टिप्पणी की, जिससे आहत होकर छात्रों ने विरोध किया और माफी मांगने की मांग की। लेकिन जेएनयूएसयू समर्थित नेताओं ने छात्रों की भावनाओं को नजरअंदाज करते हुए यूजीबीएम बैठक को बाधित किया और विरोध करने वाले छात्रों को धमकाया।

घटना के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) के जेएनयू इकाई अध्यक्ष राजेश्वरकांत दुबे ने कहा कि वामपंथी छात्रों ने भगवान श्रीराम का अपमान किया और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। जेएनयू प्रशासन को इस तरह के आपत्तिजनक व्यवहार के लिए जिम्मेदार छात्रों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि विश्वविद्यालय की छवि को बदनामी से बचाया जा सके। घटना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए जेएनयू इकाई की मंत्री शिखा स्वराज ने कहा कि महिलाओं के मुद्दों पर चर्चा के बावजूद एक भी महिला प्रतिनिधि को मंच न देना, वामपंथी छात्रों की मानसिकता को दर्शाता है। ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

भारतरत्न नानाजी देशमुख की जयंती पर देशव्यापी सेवा सप्ताह का आयोजन

भारतरत्न नानाजी देशमुख की जयंती के अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) आयाम सेवार्थ विद्यार्थी ने गत 11 अक्टूबर से 18 अक्टूबर के मध्य पूरे देश में सेवा सप्ताह का आयोजन किया। इस दौरान नानाजी देशमुख के प्रेरणादायक जीवन और समाज सुधार के प्रति उनके समर्पण को समझने और उनके विचारों को आत्मसात करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

सेवार्थ विद्यार्थी का मानना है कि नानाजी का जीवन, समाज सेवा की दिशा में एक प्रेरणास्त्रोत के रूप में है और युवाओं को उनकी शिक्षाओं से लाभ प्राप्त कर समाज सेवा की भावना को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। सेवा सप्ताह के दौरान देश के 32 प्रांतों में नानाजी देशमुख के योगदान और उनके विचारों पर आधारित संगोष्ठियां आयोजित की गईं। हर प्रांत में सेवार्थ विद्यार्थी के कार्यकर्ताओं ने नानाजी देशमुख के आदर्शों को जन-जन तक पहुंचाने का कार्य किया, ताकि समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जा सके। संगोष्ठियों के माध्यम से न केवल नानाजी के जीवन की गाथा पर चर्चा की गई, बल्कि आनंदमय और सार्थक छात्र जीवन पर भी जोर दिया गया। साथ ही छात्र जीवन में नैतिकता, अनुशासन, और समाज के प्रति उत्तरदायित्व को भी विशेष रूप से समझाया गया।

सेवा सप्ताह के दौरान नशा मुक्ति अभियान, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन (सीपीआर) प्रशिक्षण, भाषण प्रतियोगिता, नुक्कड़ नाटक और निःशुल्क चिकित्सा शिविर जैसे विभिन्न जनहितकारी कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। इन गतिविधियों के माध्यम से सेवार्थ विद्यार्थी ने समाज को सेवा का महत्व समझाने और उन्हें भी समाज सेवा में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास किया। नशा मुक्ति अभियान के माध्यम से युवाओं को नशे से दूर रहने की प्रेरणा दी गई और इसके दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया गया। नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से आम जनता को सामाजिक समस्याओं और उनके समाधान की दिशा में जागरूक किया गया, ताकि वह स्वयं को समाज की बेहतरी के लिए समर्पित कर सकें।

सेवा सप्ताह में 4,603 से अधिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया, जो कि सेवार्थ विद्यार्थी के प्रति समाज के विश्वास और समर्थन का परिचायक है। कार्यकर्ताओं ने न केवल शहरी क्षेत्रों में, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों के बीच पहुंच कर सेवा कार्यों को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सेवार्थ विद्यार्थी के कार्यकर्ताओं ने अधिकतम जनभागीदारी सुनिश्चित की, ताकि नानाजी देशमुख के विचारों और सेवा के संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सके। नानाजी देशमुख का विचार था कि एक सशक्त और आत्मनिर्भर समाज ही देश को सुदृढ़ बना सकता है। उनके इन्हीं आदर्शों को ध्यान में रखते हुए, सेवार्थ विद्यार्थी ने सेवा सप्ताह में अनेक गतिविधियों के माध्यम से समाज में आत्मनिर्भरता, सहयोग, और सेवा भावना का प्रसार किया।

सेवार्थ विद्यार्थी के अखिल भारतीय सह संयोजक यश कुमार सिंह ने बताया कि नानाजी देशमुख के समाज सुधारक विचारों को आत्मसात करते हुए, सेवार्थ विद्यार्थी ने सेवा सप्ताह के दौरान कई सेवा कार्यों के माध्यम से सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन किया है। सेवार्थ विद्यार्थी समाज के हर स्तर पर सेवा भावना का संचार करते हुए नानाजी के सपनों वाले सशक्त समाज को निर्मित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सेवा सप्ताह के माध्यम से, सेवार्थ विद्यार्थी ने न केवल समाज सेवा का उदाहरण प्रस्तुत किया बल्कि एक प्रेरणादायक संदेश भी दिया कि हर व्यक्ति में समाज के प्रति कुछ न कुछ योगदान देने की शक्ति और इच्छा होती है। नानाजी देशमुख के विचारों को आत्मसात कर सेवार्थ विद्यार्थी का उद्देश्य एक ऐसा समाज का निर्माण करना है, जिसमें हर व्यक्ति समाज सेवा के कार्यों में स्वयं को शामिल कर सके और अपने आस-पास सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए अग्रसर हो। ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

। उत्तर प्रदेश ।

लोक सेवा आयोग ने स्वीकारी अभ्यर्थियों की मांग

एक ही दिन में होगी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रादेशिक सिविल सेवा (पीसीएस) की प्रारंभिक परीक्षा को एक ही दिन और एक ही बार में कराने का निर्णय लिया है। साथ ही समीक्षा अधिकारी (आरओ) एवं सहायक समीक्षा अधिकारी (एआरओ) के लिए होने वाली परीक्षा को स्थगित करके एक समिति का गठन किया है, जो परीक्षा के प्रारूप पर निर्णय लेगी। आयोग ने यह निर्णय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) के नेतृत्व में छात्रों द्वारा किए गए आंदोलन के बाद राज्य सरकार के निर्देश पर लिया है।

अभाविप ने आयोग के निर्णय का स्वागत किया है। साथ ही आरओ एवं एआरओ परीक्षा संबंधी अभ्यर्थियों की चिंताओं का निराकरण कर यह परीक्षा भी जल्द आयोजित कराने की मांग की है। अभाविप काशी प्रांत के प्रांत मंत्री अभय प्रताप सिंह ने कहा कि यह निर्णय अभ्यर्थियों की जीत है। आयोग ने अभ्यर्थियों की मांगों को संज्ञान में लेते हुए संवाद स्थापित करने के पश्चात यह निर्णय लिया है। परीक्षा की शुचिता एवं विशिष्टता को बनाए रखने हेतु यह आवश्यक कदम था। अब अभ्यर्थी निश्चित होकर परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। आयोग के नए निर्णय के अनुसार पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा आगामी 22 दिसंबर को आयोजित की जाएगी।

इससे पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस प्रारंभिक-2024 और आरओ/एआरओ प्रारंभिक-2023 परीक्षाओं को दो दिनों में दो शिफ्ट में आयोजित करने का निर्णय लिया था। इस निर्णय का अभ्यर्थी लगातार विरोध कर रहे थे। अपनी मांग को लेकर अभ्यर्थी सड़कों पर उतर आए, जिसके बाद पुलिस ने अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया था, जिससे स्थिति बिगड़ती जा रही थी। अभाविप के नेतृत्व में अभ्यर्थी यूपीपीएससी की परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन सिस्टम खत्म करने की मांग पर अड़े हुए हैं क्योंकि आयोग के नॉर्मलाइजेशन सिस्टम का तरीका निष्पक्ष नहीं है।

क्या है नॉर्मलाइजेशन विवाद

हाल ही में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रतियोगी परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन सिस्टम लागू करने को लेकर एक नोटिस जारी किया था। इसमें कहा गया था कि अगर कोई परीक्षा दो या दो से अधिक दिन तक चलती है तो उनका मूल्यांकन परसेंटाइटल के आधार पर किया जाएगा। लेकिन अगर एक दिन ही परीक्षा होगी तो उसमें नार्मलाइजेशन सिस्टम लागू नहीं होगा। ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

ABVP and JU Host India-Germany Youth Dialogue in Bengaluru

Facilitated by Konrad Adenauer Stiftung

In a significant effort to boost international cooperation, the Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad (ABVP) and Germany's Junge Union (JU), the youth wing of the Christian Democratic Union (CDU), recently conducted the India-Germany Youth Dialogue in Bengaluru. The event, facilitated by Dr. Adrian Haack, India Director of Konrad Adenauer Stiftung (KAS), centered on policy advocacy, education, and technology, underscoring common interests shared by youth in both countries.

The dialogue, aimed at enhancing Indo-German cooperation, featured two key segments: a private session involving ABVP and JU youth leaders, and a public panel discussion with Bengaluru's youth. This format created an opportunity to address pressing global challenges and explore avenues for collaboration.

Ashish Chauhan, National Organising Secretary of ABVP, led the Indian delegation, joined by Yagyawalkya Shukla National General Secretary, and other senior members. Representing Germany, Ms. Karoline Sophie Czychon, State Chairwoman of Junge Union Niedersachsen, led a team that included Anna Catherina Frohn, Henrike-Catherine Börstling, Christian Führer, MLA, and Johannes Van Wieren.

The discussions saw ABVP articulating

India's stance on education, security, and the transformative potential of technology for youth-led initiatives. The JU delegation highlighted Germany's strategies on these matters, stressing the importance of India's role in European and West Asian security.

The dialogue highlighted the critical role of youth in driving international partnerships and fostering positive transformation. Both delegations expressed a strong commitment to ongoing collaboration, emphasizing the ability of youth to bridge cultural divides, create new opportunities, and contribute to a more interconnected world.

The success of the event sets the stage for further India-Germany youth dialogues, aimed at deeper cooperation in areas such as education reform, technological advancement and security. The dialogue reinforced the significance of international exchanges in shaping future policy that impacts both countries.

Dr. Adrian Haack, representing KAS, described the dialogue as a unique opportunity to bring together young leaders from two distinct yet interconnected backgrounds. He highlighted the importance of finding common ground on global issues and emphasized the need for youth-driven engagement to foster lasting partnerships between India and Germany.

In a world facing complex challenges that require global solutions, the India-Germany Youth Dialogue in Bengaluru served as a reminder of the crucial role youth play in influencing policy, advocating for change, and building a more inclusive future. The partnership between ABVP and Junge Union is a positive step towards strengthening Indo-German relations, deepening mutual understanding, and finding collaborative solutions to common challenges.

Both delegations concluded the event with a commitment to a continuous dialogue, aspiring to harness the potential of their young populations to drive progress. This gathering is seen as a key milestone in the effort to create a more interconnected, inclusive, and cooperative global society. ■

(Rashtriya Chhatrashakti Team)

SHoDH Hosts Inspiring "Research for Radiant Bharat" Conclave in Bhagyanagar

The Students for Holistic Development of Humanity (SHoDH) Telangana organized an engaging and thought-provoking Research Scholars' Conclave, titled "Research for Radiant Bharat," on the 8th and 9th of November at Jawaharlal Nehru Technological University, Hyderabad (JNTU-H). This significant event was organized in collaboration with the Indian Council of Social Science Research (ICSSR), Vidyarthi Seva Samithi (VSS), JNTU-Hyderabad, and ICFAI, with the support of the Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad (ABVP).

The conclave aimed to advance the culture of research and innovation with objectives that included understanding the research process, promoting ethical publication practices, building networks for interdisciplinary studies, and exploring opportunities for academic careers in research. Scholars, academicians, and leading figures from various fields gathered for the event, sharing valuable insights on the current and future landscape of higher education and research in India.

Professor Manish R. Joshi, Secretary of the University Grants Commission (UGC), delivered a powerful keynote address,

urging the development of innovative research practices that align with global standards. His address resonated with the audience, highlighting the need for a forward-thinking education system to strengthen India's academic community.

Distinguished academicians contributed to the discourse, with Professor T. Mrunalini from Osmania University advocating for an integration of the Indian Knowledge System (IKS) with modern research. Her vision emphasized the importance of blending traditional knowledge with contemporary research, providing a culturally rich academic approach. Former Vice-Chancellor of the University of Hyderabad, Professor Appa Rao, focused on the theme of "Vikasit Bharat" (Developed India), encouraging impactful research that contributes to national development.

A notable highlight was the participation of Shri A. Rajarajan, Director of the Satish Dhawan Space Centre, Sriharikota. Shri Rajarajan, a Distinguished Scientist, inspired young scholars to delve into research that could further India's advancements in space and science. His address celebrated India's achievements in space exploration, motivating attendees to contribute to the nation's scientific endeavors.

Shri B.S. Murthy, Director of IIT Hyderabad, emphasized the value of collaborative efforts in education and research, while Professor Dr. B. Vishnu Vardhan from JNTU provided practical guidance on effective research publication, aiding scholars in gaining international visibility. Adding to the global perspective, Surabhi Hodigere, a policy researcher and Harvard University alumna, discussed international research fellowships and opportunities, encouraging Indian scholars to pursue global research avenues.

The conclave also highlighted the contributions of SHoDH and ABVP in fostering research and nation-building. In the Valedictory Session, Shri Ashish Chauhan ji, National Organising Secretary of ABVP, emphasized the role of India's rich cultural and intellectual heritage in shaping a "Vikasit Bharat." He inspired scholars to draw from India's deep-rooted traditions as they advance in research and academia.

The two-day event saw active participation from 240 delegates representing 22 universities and institutions. The conclave provided a platform for networking, idea-sharing, and collaboration through discussions and poster presentations, fulfilling its mission to inspire research for a "Radiant Bharat."

The two-day event saw active participation from 240 delegates representing 22 universities and institutions. The conclave provided a platform for networking, idea-sharing, and collaboration through discussions and poster presentations, fulfilling its mission to inspire research for a "Radiant Bharat."

The event concluded with a vote of thanks by Sreedhar, Telangana State Convenor of SHoDH, who expressed gratitude to all contributors, including speakers, participants, and collaborators. Delegates left the conclave with a renewed commitment to drive impactful research that will contribute to the betterment of society and the development of the nation.

This event highlights the spirit and goals of the Research Scholars' Conclave, showcasing the contributions of experts and encouraging the future generation of scholars in India. ■

(Rashtriya Chhatrashakti Team)

Donald Trump's Presidency and its far-reaching impact on India

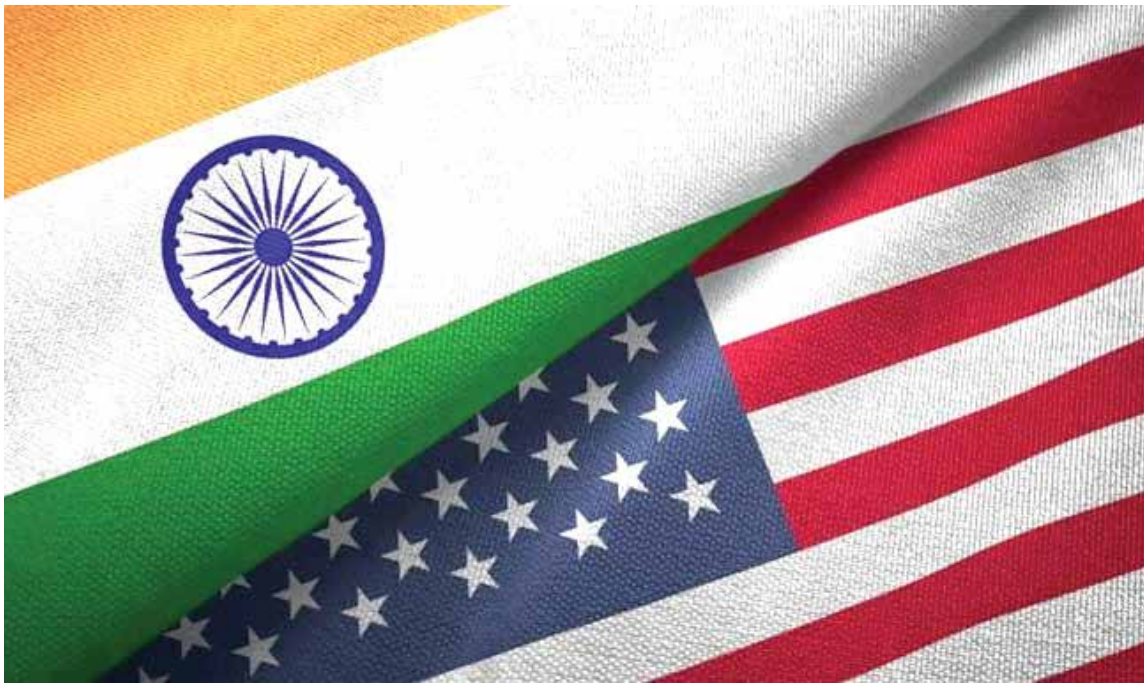

■ Dr. Arvind Deshmukh

Donald Trump's return as the 47th President of the United States marks a remarkable comeback, representing one of the most significant political returns in U.S. history. His re-election has raised questions and optimism for India, given the strong Indo-U.S. ties built during his first term and his notable rapport with Indian Prime Minister Narendra Modi. The Trump-Modi relationship brought significant milestones to the Indo-U.S. partnership, rooted in a shared vision for security and economic cooperation, particularly in the Indo-Pacific, a region critical to countering China's influence.

Historically, Indo-U.S. relations have evolved from a period of ambivalence to one of strategic partnership. Since the Cold War era, when India maintained a non-aligned stance, relations have transformed, especially post-2000, into a closer alliance bolstered by shared democratic values and economic interests. During Trump's initial term, the partnership reached new heights, with key achievements like the Quadrilateral Security Dialogue (QUAD) revitalized to counterbalance China's rising influence. Additionally, Trump's 2017 National Security Strategy underscored India as a key partner, emphasizing a "free and open Indo-Pacific" strategy that aligns with India's geopolitical ambitions.

India's strategic importance is undeniable, not only as a regional power but also as a key player in global trade. The U.S. recognizes that fostering a positive relationship with India is crucial to maintaining a competitive stance against China. Trump's firm stance against China aligns with India's interests, and his connections with Russian President Vladimir Putin could ease Western pressure on India regarding its ties with Russia. Additionally, Trump's presidency has been characterized by minimal commentary on India's domestic politics, allowing India to navigate its internal matters without external scrutiny.

Trump's return could see a renewed focus on trade agreements with India, potentially amplifying tariffs as part of his "America First" approach. Trump's views on tariffs are mixed; he has historically used them as leverage but is likely to pursue selective tariff reductions to promote sectors where Indo-U.S. trade synergy is strong, such as pharmaceuticals, IT, and defense.

A Trump presidency could bring varied trade implications for India. According to Moody's, India's economy stands to benefit from Trump's presidency due to the escalating US-China tensions and

potential investment restrictions emerging in critical sectors. This shift in power dynamics could lead to a reallocation of trade and investment flows away from China, creating new opportunities for India and other ASEAN countries. Sectors like pharmaceuticals, IT and manufacturing may benefit from reduced barriers and stronger collaboration on technology and intellectual property. The auto sector, however, may encounter challenges if Trump imposes tariffs on automobile imports to protect U.S. manufacturers, potentially impacting Indian car exports to the U.S. Conversely, a strengthened defense relationship could benefit India's defense manufacturing under Make in India, as Trump may prioritize defense sales as part of security alliances.

From a global energy perspective, Trump's policies may also impact India, especially if he prioritizes fossil fuels over renewable energy. India, which relies heavily on oil imports, could face challenges if Trump's policies lead to increased global oil prices or reduced U.S. support for renewable energy collaborations. However, there could be positive outcomes for India's fossil fuel sector, as increased U.S. fossil fuel production may lead to a more stable supply chain for India.

On 5th August 2019, the historical date when Article-370 was abrogated, India witnessed a varying response from the United States. The response of the Republican Party was mostly favorable where they viewed the abrogation of Article-370 as a sovereign decision by India to integrate Jammu and Kashmir more fully into the country. Many Republicans saw this move as a step towards strengthening India's territorial integrity and combating terrorism in the region. They believed that the abrogation would help bring stability and development to Jammu and Kashmir, aligning with their broader foreign policy goals of supporting democratic allies and countering terrorism. The Democratic Party in the United States, however, had a mixed response. While some Democratic leaders were recognizably discomforted by the bold move made by the Government of India, the official stance of the Democratic Party was not uniformly critical, as they also recognized the complexity of the situation and the sovereignty of India in making decisions about its internal matters. Therefore, on the Kashmir issue, Trump's stance might align more closely with India's, given his inclination to support India's internal sovereignty matters. His administration could continue to lend diplomatic support to India, countering external criticism and pressuring Pakistan on terrorism issues-a stance that could aid India in stabilizing Jammu and Kashmir.

Therefore, on the Kashmir issue, Trump's stance might align more closely with India's, given his inclination to support India's internal

sovereignty matters. His administration could continue to lend diplomatic support to India, countering external criticism and pressuring Pakistan on terrorism issues—a stance that could aid India in stabilizing Jammu and Kashmir.

The presidential campaign for the 47th presidency of the United States witnessed the emergence of young Hindu Americans with a favorable view of India. Vivek Ramaswamy, an American entrepreneur and son of Indian immigrant parents from Kerala has been appointed by President- elect Donald Trump to co-lead the newly proposed Department of Government Efficiency alongside Elon Musk. Vivek has expressed admiration for India's economic growth and leadership under Prime Minister Narendra Modi. He believes that

Hindu American, Tulsi Gabbard has also found a highly respectable place in Trump's upcoming Cabinet as the Director of National Intelligence (DNI), a role that oversees the U.S. Intelligence Community. Tulsi was the first Hindu member of the US Congress, a fact she proudly carries on her sleeve. Tulsi is also a veteran of the U.S. Army National Guard.

India's impressive GDP growth is largely due to the opening of markets and embracing capitalism, which he sees as the best system to lift people out of poverty. Vivek also acknowledges that India, like any nation, has its challenges, but he is optimistic about its direction. He supports a stronger relationship between the United States and India, viewing it as beneficial for both countries. Another Hindu American, Tulsi Gabbard has also found a highly respectable place in Trump's upcoming Cabinet as the Director of National Intelligence (DNI), a role that oversees the U.S. Intelligence Community. Tulsi was the first Hindu member of the US Congress, a fact she proudly carries on her sleeve. Tulsi is also a veteran of the U.S. Army National Guard, having served in Iraq and Kuwait. During her tenure, she was known for her anti-war stance and her criticism of U.S. foreign policy, particularly in the Middle East. Tulsi has been vocal about her faith and has often spoken about how her faith influences her values and principles, including her commitment to non-violence and vegetarianism. She has also been an advocate for religious freedom and has spoken out against atrocities committed against Hindus and other minorities in regions like Pakistan and Bangladesh. Vivek and Tulsi's appointment in the Trump administration is of great significance for India and a step forward to strengthening bilateral relations, which could result in greater diplomatic understanding and support in areas of cultural and strategic significance.

Immigration policies under Trump will likely reflect his earlier stance on controlling immigration, which had mixed effects on India. From 2016 to 2020, Trump's administration placed tighter restrictions on H-1B visas, affecting many Indian tech professionals. A renewed Trump administration could continue this trend, impacting Indian IT professionals but also potentially reforming the H-1B program to focus on higher-skill roles, which could benefit skilled Indian workers in the long run.

In conclusion, Trump's potential second term holds a promising yet complex future for India-U.S. relations. While trade challenges and immigration policies may present hurdles, Trump's pro-India stance, coupled with a strong personal rapport with PM Modi, indicates a continuation of the strategic alignment between India and the U.S. This partnership could not only benefit both countries economically and strategically but also support stability in the Indo-Pacific and provide a counterbalance to China's growing influence in the region. ■

जांच समिति का खुलासा

वीआईटी विश्वविद्यालय में अवैध रूप से हुई कुलगुरु की नियुक्ति

सीहोर स्थित वीआईटी विश्वविद्यालय के छात्रावास में स्नान करती छात्राओं का वीडियो बनाने एवं वायरल करने की घटना के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) के आंदोलन के बाद विश्वविद्यालय में व्याप्त अनियमितताएं एवं धांधलियों उजागर होने लगी हैं। अभाविप के विरोध के बाद गठित जांच कमेटी ने खुलासा किया है कि विश्वविद्यालय के कुलगुरु की नियुक्ति अयोग्य तरीके से की गई है। इसके बाद भी कुलगुरु की विरुद्ध कोई कार्रवाई अब तक नहीं की गई है और शासन-प्रशासन के सभी नियमों को ताक पर रखकर विश्वविद्यालय का संचालन किया जा रहा है।

जानकारी हो कि गत अक्टूबर माह में छात्राओं का वीडियो वायरल होने के बाद दोषियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई बल्कि 74 अन्य विद्यार्थियों को निलंबित कर दिया गया। इनमें से 12 छात्रों को स्थाई रूप से निलंबित किया गया, जबकि अन्य को छह माह से लेकर एक वर्ष तक के लिए शिक्षा से वंचित कर दिया गया। इसके विरोध में अभाविप ने जब आंदोलन किया तो एक जांच समिति का गठन करके जांच प्रक्रिया आरंभ की गई।

जांच समिति ने खुलासा किया कि निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग ने वीआईटी विश्वविद्यालय के कुलगुरु की नियुक्ति अयोग्य बताई है। मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम-2007 यथासंशोधित 2013 एवं 2016 में कुलपति की नियुक्ति धारा-17 के अंतर्गत कुलगुरु की नियुक्ति के प्रावधान किए गए हैं। निजी विश्वविद्यालयों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का जब

समिति ने जांच की तो पाया गया कि अधिनियम की धारा-17 के अंतर्गत कुलगुरु की नियुक्ति के वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं किया गया। विश्वविद्यालय में कुलगुरु डा. ए. सेंथिल कुमार की नियुक्ति अधिनियम के विपरीत की गई, जो कि मापदंडों के अनुरूप नहीं है। इसके लिए विश्वविद्यालय ने निर्धारित प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित नहीं किया।

समिति ने अपनी सिफारिश में कुलगुरु को तत्काल पदच्युत करते हुए विश्वविद्यालय परिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत योग्यता एवं मापदंड के अनुसार कार्यवाहक कुलगुरु की तत्काल नियुक्ति करने के लिए भी कहा। साथ ही आदेश पर तत्काल कार्रवाई करने के लिए पंद्रह दिन की समय सीमा भी निर्धारित की गई। इसके बाद भी कुलगुरु के विरुद्ध कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई है और शासन-प्रशासन के सभी नियमों को ताक पर रखकर विश्वविद्यालय का संचालन किया जा रहा है। इसके विरोध में अभाविप पुनः आंदोलन करने की तैयारी कर रही है। ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

। अरुणाचल प्रदेश ।

'राष्ट्र की उन्नति के लिए काम कर रही है अभाविप'

अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले स्थित तेजू इंजीनियरिंग कालेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) का 12वां प्रांत अधिवेशन आयोजित किया गया। अधिवेशन में राज्य के उपमुख्यमंत्री चौना मीन ने मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। सम्मेलन में शिक्षा, छात्र सशक्तिकरण, नेतृत्व और राष्ट्रीय गौरव पर विस्तृत चर्चा की गई।

मुख्य अतिथि एवं राज्य के उपमुख्यमंत्री चौना मीन ने अपने संबोधन में अभाविप की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि विद्यार्थियों को राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। उन्होंने प्रदेश के विभिन्न समुदायों, विशेष रूप से स्वदेशी जनजातियों की एकता की महत्ता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि इन समुदायों की भागीदारी से राज्य की सामूहिक राष्ट्रवाद और देशभक्ति की भावना को बल मिलता है।

गत 8 से10 नवंबर तक आयोजित सम्मेलन में अभाविप के राष्ट्रीय सह-संगठन मंत्री गोविंद नायक ने कहा कि इस सभागार का नामकरण अरुणाचल प्रदेश के स्वाभिमान और गौरव के प्रतीक क्रांतिकारी कैशा मन्यु के नाम पर किया गया है। अधिवेशन में क्रांति वीरों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसके माध्यम से अमर बलिदानियों को याद किया गया। उन्होंने बताया कि गत वर्ष अभाविप की सदस्य संख्या 50 लाख से अधिक हो चुकी है और संगठन का विस्तार देश के प्रत्येक कोने में हो चुका है। सम्मेलन में अभाविप, अरुणाचल प्रांत के मंत्री श्रीकांतराम ने संगठन की भूमिका को स्पष्ट करते हुए कहा कि अभाविप एक ऐसा संगठन है जो न केवल शिक्षा और छात्र हित में काम करता है, बल्कि जब भी देश की अस्मिता पर संकट आता है या महिलाओं के अधिकारों की रक्षा का प्रश्न आता है तो अभाविप कार्यकर्ता सबसे पहले सामने आता है।

अभाविप के प्रांत अध्यक्ष डा. राजेन ने संगठन की कार्यप्रणाली और उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि अभाविप का उद्देश्य केवल राजनीतिक नेताओं का निर्माण नहीं है। ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

। हिमाचल प्रदेश ।

संस्कृति संरक्षण का संकल्प

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) हिमाचल प्रदेश का 45वां प्रदेश अधिवेशन हमीरपुर स्थित गौतम महाविद्यालय में संपन्न हुआ। तीन दिवसीय अधिवेशन में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए छात्रों, कार्यकर्ताओं और शिक्षा क्षेत्र के प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। अधिवेशन का उद्देश्य प्रदेश में शिक्षा जगत में आ रहे बदलावों और चुनौतियों पर चर्चा करके ठोस कार्ययोजना तैयार करना था। अधिवेशन में अभाविप की नव प्रदेश कार्यकारिणी का गठन भी किया गया।

गत 7 नवंबर से 9 नवंबर तक आयोजित अधिवेशन के उदघाटन सत्र को संबोधित करते हुए दिव्य प्रेम सेवा मिशन के संस्थापक एवं अध्यक्ष आशीष गौतम ने कहा कि भारत और विद्यार्थी परिषद एक ही शब्द है। राष्ट्र सेवा के काम को अभाविप ने 75 साल पहले स्वीकार किया था और इस पर शोध होना चाहिए।

अधिवेशन में राज्य के मौजूदा शैक्षणिक परिदृश्य पर गहन चर्चा के साथ ही कई प्रस्ताव पारित किए गए। इनमें प्रदेश के उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने, छात्रों के समग्र विकास के लिए गतिविधियों को बढ़ावा देने और नए रोजगारोन्मुख पाठ्यक्रमों की आरम्भ करने प्रस्ताव शामिल हैं। तीन दिवसीय अधिवेशन के दौरान युवाओं को शिक्षा के क्षेत्र में आ रही चुनौतियों से परिचित कराते हुए उनमें नेतृत्व क्षमता के विकास पर भी जोर दिया गया। अधिवेशन के दौरान वक्ताओं ने प्रदेश में शिक्षा प्रणाली के सुधार की आवश्यकता पर बल दिया। साथ ही निर्णय लिया गया कि अभाविप आने वाले वर्षों में प्रदेश के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में डिजिटल सुविधाएं बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहेगी। ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

तेजू : 12 वें प्रांत अधिवेशन को संबोधित करते हुए अरुणाचल प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री चौना मीन, मंचासीन हैं अभाविप के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री गोविंद नायक, प्रांत अध्यक्ष डा. राजेन एवं अन्य पदाधिकारी

हमीरपुर : 45 वें प्रांत अधिवेशन का शुभारंभ करते हुए दिव्य सेवा मिशन के अध्यक्ष आशीष गौतम, अभाविप महामंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल, आईआईटी (मंडी) के निदेशक लक्ष्मीधर बोहरा, अभाविप प्रांत अध्यक्ष राकेश शर्मा, स्वागत समिति अध्यक्ष भूपेन्द्र बनयाल, मंत्री नवीन शर्मा एवं अन्य पदाधिकारी

RNI NO.: DELBIL/2017/73636
DATE OF POSTING: 10-11 NOVEMBER, 2024
DATE OF PUBLISHING: 8 NOVEMBER, 2024

POST OFFICE: NDGPO, NEW DELHI
POSTING REGISTRATION NO. DL(C)-11/1409/2024-26

World's largest student organisation

ABVP

70TH NATIONAL CONFERENCE

22-24 NOVEMBER 2024
GORAKHPUR

Dr. Rajsharan Shahi
National President, ABVP

Yagywalkya Shukla
National General Secretary, ABVP